राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 33 अंक 7 अक्टूबर 2011 नयी दिल्ली मूल्य 5 रु. पृष्ठ 32

पाकिस्तान फिर दोहराएगा एक और कारगिल?

भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी है व्यापक लडाई

भ्रष्टाचार के विरूद्ध... युवा
YOUTH ...AGAINST CORRUPTION

लोग अब गरीब नहीं रहेंगे !

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

स्त्रोत–केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद–वृद्धि दर 11.49 प्रतिशत,*

विगत 5 वर्षों में औसत विकास दर 10.89 प्रतिशत
देश में सर्वाधिक तेजी से विकास करता राज्य

छत्तीसगढ़ में है भारत का–

- 20% आयरनओर
- 17% कोयला भण्डार
- 12% डोलोमाइट
- 12% वन
- 100% टिन

छत्तीसगढ़ में होता है भारत का–

- 16% खनिज उत्पादन
- 27% स्टील एवं स्पांज आयरन
- 30% एल्युमिनियम उत्पादन
- 15% सीमेंट उत्पादन

डॉ.रमन सिंह
मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

सम्पादक
आशुतोष

सम्पादक मण्डल
अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-43098248
ईमेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाइट : www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली-07 से प्रकाशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के. 30 नवीन शाहादरा, दिल्ली- 32 द्वारा मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय :
"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

अनुक्रमणिका

विषय	पृ.सं.
संपादकीय	04
भ्रष्ट लोगों से दूषित हुई व्यवस्था	05
भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी है व्यापक लड़ाई –सुनील आंबेकर	08
शिक्षा का व्यावसायीकरण –रुपम गौर	11
लोग अब गरीब नहीं रहेंगे –अवनीश सिंह	15
क्या पाकिस्तान कश्मीर में फिर दोहराएगा एक और कारगिल? –नरेन्द्र सहगल	17
म.प्र. छात्रसंघ चुनाव में अभाविप की ऐतिहासिक विजय	20
भ्रष्टाचार देश की बड़ी समस्या –सुनील कुमार बंसल	22
समग्र क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण	28

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य से प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है। स्वयंपूर्ण, स्वायत्त और स्वावलंबी संगठन होते हुए भी राष्ट्रवाद की जिस विचार सरणी से अभाविप का गर्भनाल संबंध है उसका मूलस्त्रोत संघ ही है।

तत्कालीन परिस्थितियों का भारतीय दृष्टि से विश्लेषण करते हुए संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने अनुभव किया कि पश्चिम की पद्धति से प्रेरित और प्रभावित संगठन स्वतंत्रता के बाद भी भारत को राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप गढ़ नहीं सकेंगे। इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय चिन्तन, दर्शन की गहरी समझ रखने वाले तथा राष्ट्रीय विचार के लिये प्रतिबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं की मालिका तैयार हो।

इसी प्रक्रिया में से सर्वप्रथम राष्ट्र सेविका समिति तथा बाद में अन्य अनेक संगठनों जन्म हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात देश के युवाओं को आदर्श नागरिक के रूप में तैयार करने तथा उनकी ऊर्जा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में नियोजित करने की बात कुछ युवाओं के मन में आयी और विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। गत ६३ वर्षों में परिषद ने इस क्षेत्र में यशस्वी भूमिका निभायी है।

आज इस इतिहास को स्मरण करने का प्रसंग अनायास ही नहीं आया है। अवसर है विजयादशमी, जिस दिन वर्ष १९२५ में डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ के मुख्यालय नागपुर में इस अवसर पर प्रतिवर्ष गणवेश धारी स्वयंसेवकों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसे संघ के सरसंघचालक संबोधित करते हैं। प्रतिबंध काल को छोड़ दें तो यह एक परंपरा ही है।

इस वर्ष ६ अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव, स्पष्ट तथा निर्भय राष्ट्रीय दृष्टि की अनुपस्थिति से उपजी हतबलता, ढुलमुल नीति, दब्बूपन, अपनी जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति, स्वार्थकारण आदि बीमारियों से ग्रस्त राजनीति समाज में केवल निराशा व अविश्वास का वातावरण ही उत्पन्न कर रही है।

राष्ट्रजीवन के सभी अंगों में परकीय प्रवृत्ति की आक्रामक व घातक घुसपैठ को रोककर संपूर्ण राष्ट्र को सशक्त व समरस बनाकर चुनौतियों पर मात करते हुए वैभव पथ पर आगे बढ़ाने का दायित्व अब समाज को ही सम्भालना पड़ेगा।

आसुरी प्रवृत्ति के दमन के लिये देवों द्वारा की गयी सम्मिलित तपस्या के फलस्वरूप सर्वविजयी, कल्याणकारी महाशक्ति दुर्गा प्रकट हुई थी व सत्प्रवृत्ति विजयी हुई थी। फिर एक बार परिस्थिति सज्जनों के उस सम्मिलित विजिगीषु पुरुषार्थ की मांग कर रही है। विजिगीषु पुरुषार्थ का यह आह्वान समय की मांग को रेखांकित करता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाज में अनेक दिशा और दर्शन वाले समूह एक-साथ आ जुटे हैं। परिवर्तन की बहस चल पड़ी है । परिषद भी इसमें पूरी शक्ति से लगी है। लेकिन सभी मिलकर भी अभी अपेक्षित विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर सके हैं। विजिगीषु पुरुषार्थ का आह्वान परिषद कार्यकर्ताओं के लिये पाथेय है जिसके बल पर राष्ट्र पुनर्निर्माण का शिलालेख लिखा जा सकेगा।

'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्प'

भ्रष्ट लोगों से दूषित हुई व्यवस्था

दिल्ली २५ सितंबर। यूथ अगेन्स्ट करप्शन के तत्वाधान में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सारे देश में कार्यक्रम हुए। दिल्ली में ६ स्थानों में विचार गोष्ठियां हुईं जिसमें मुख्य विचार गोष्ठी न्यू रोहतक रोड करोल बाग स्थित नवहिंद स्कूल के सभागार में आयोजित की गई। पूर्व सी.बी.आई. निदेशक श्री जोगिंदर सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता श्री अश्वनी महाजन और यू.आर.जे.ए. के चेयरमैन श्री संजय कौल ने संबोधित किया।

गोष्ठी में बोलते हुए संजय कौल ने बताया कि व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होती अपित लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, यह समझना आवश्यक है। ब्रॉडकास्टिंग बिल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा एक नीति के अनुसार लोगों को जबरदस्ती विज्ञापन दिखाए जाते हैं, दर्शक इन्हें देखने के लिए विवश है क्योंकि टेलीविजन चैनलों एवं कंपनियों की सहमति से एक ही समय में सभी जगह एक से विज्ञापन आते है। आपकी आजादी छीन ली गई है। भ्रष्टाचार को समझने के लिए उसकी जड़ पर जाना जरूरी है। आज से २० साल पहले आय में इतना अधिक अंतर नहीं था। यह कैसे हुआ यह जानना आवश्यक है। उदारीकरण के दौर में नीतियां ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बनने लगीं। बिजली विभाग को घाटे में दिखा तथा जनता की सुविधा के नाम पर उसका निजीकरण किया गया। आज यह निजी बिजली कंपनियां लाभ में चल रहीं हैं लेकिन कागजों में घाटा दिखा कर बिजली दरों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज आवश्यकता भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतियों को बनाने की है।

श्रीमती रश्मि सिंह ने २ जी स्पैट्रम घोटाले पर चर्चा करते हुए कहा देश के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है जिसके तार दूरसंचार मंत्रालय से लेकर पी.एम.ओ तक पहुंचे हुए हैं। इस घोटाले में जिस मूल्य पर स्पैक्ट्रम सरकार में बैठे मंत्रियों के परिचितों को बांटे गए उससे दस गुना अधिक में उन्होंने वह विदेशी कंपनियों को बांटे। इससे देश को इतना अधिक नुकसान हुआ है जिससे देश में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में ६ गुनी वृद्धि की जा सकती थी। ४ गुना शिक्षा और रोजगार के साधनों को बढ़ाया जा सकता था।

बोफोर्स कांड के लगभग सभी खुलासे सरकार के अति दबाव के बावजूद करने वाले सरदार श्री जोगिंदर सिंह ने अपने उदबोधन में कहा कि हमारे संविधान में सीबीआई सरकार का एक अंग है तथा वह उसकी अनुमति से ही कार्य करेगी। सीबीआई को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी सरकार से पूछना पड़ता है। जब सरकार में बैठे लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं तो सी.बी.आई से जांच करा उन्हें सजा दिलाना असंभव सा है। वास्तव में हमारे देश में कानून ही सारे गुण्डों-बदमाशों को छोड़ने के लिए बने हुए हैं। एक के बाद एक अपील करने का

विधान है। अण्णा हजारे की मुहिम बिल्कुल ठीक है। किन्तु उनकी इस मुहिम का कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सरकार में बैठे लोग हों या विपक्षी पार्टियां, कभी भी अपने गले में लोकपाल का फंदा नहीं डालना चाहेंगी। इसलिए मेरे ख्याल से तो जनलोकपाल बिल पारित होना कठिन है। आज एक से डेढ़ साल विदेशों में इन्वेस्टीगेशन शुरु करने में लगता है। इसके बाद इसे लॉ मिनिस्टरी में भेजा जाता है। जब तक आपको पता चलेगा वहां का पैसा कहीं का कहीं ट्रांसफर हो गया होता है। अगर आप कुछ करना भी चाहें तो वह एक असंभव सा कार्य होगा। एक हजार केस १५ सालों से पैंडिंग पड़े है। जांच के नाम पर आरोपियों को बचने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। विदेशों में १४५६ मिलियन डॉलर ब्लैक मनी जमा है। इंग्लैण्ड और जर्मनी ने स्विटजरलैण्ड से उनके देशों की ब्लैक मनी पर टैक्स देने के संदर्भ में ब्लैक मनी धारकों के नाम न दिए जाने की शर्त मानते हुए समझौता किया है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सड़कें बनाने के लिए १०१ करोड़ प्रति किलोमीटर की दर से पैसा दिया गया। इससे कई गुना दर पर रेल मार्ग तथा एयरपोर्ट के रनवे तैयार होते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री अजय कुमार ने बताया कि अन्ना तथा बाबा रामदेव के आन्दोलन से पहले मार्च २०११ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने व्यापक प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि संघ उन सभी संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों का पूर्ण समर्थन तथा सहयोग करेगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने बताया अयोध्या आंदोलन के समय कोई भी साधारण जन यदि जय श्री राम का उद्घोष करता था तो सरकार में बैठे कथित धर्मनिरपेक्षी नेता उसे संघ का व्यक्ति कहने लगते थे, उड़ीसा में धर्मांतरण कराने वाले पादरी को जलाने वाले दारासिंह ने भी जय श्रीराम के नारे लगाए तो उसका संबंध भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोड़ा जाने लगा। पहले भारत माता की जय तथा वंदे मातरम बोलने वालों को सांप्रदायिक कहा जाने लगा था। जो भी भावनावश भारत माता का जय घोष करे तो उसे संघ से जुड़ा माना जाने लगा था तथा भगवाकरण जैसे शब्द बनाए गए। आज सरकार चुप है। अण्णा हजारे और रामदेव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वंदे मातरम एवं भारत माता की जय का सेकुलरिज्म कर दिया। आज लाखों की संख्या में लोग वंदेमातरम तथा भारत माता का जयघोष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका जन्म तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के सातवें महीने में ही जीप घोटाले के रूप में हो गया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अश्वनी महाजन ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा आज देश भर में एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने बाबा रामदेव की बात का उल्लेख कर कहा ४०० लाख करोड़ स्विटजरलैंड के बैंक खातों में जमा है। सरकार कहती है कि इसकी जानकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर जानकारी प्राप्त करने में असमर्थता दिखा रही है। जबकि वहां के राजदूत कहते हैं हमने कभी जानकारी देने से मना ही नहीं किया है आप केवल जानकारी

मांगकर तो देखिए। भारत में भ्रष्टाचार का मूल नीति निर्माण में ही है। केन्द्र सरकार की कुल योजनाओं के खर्च का वार्षिक बजट १२ लाख करोड़ का है किन्तु सभी साधनों तथा कर से वह ८ लाख करोड़ ही जुटा पाती है। २ लाख करोड़ के नोट हर वर्ष छापने पड़ते हैं जिस कारण मंहगाई बढ़ रही है। बढ़ती मंहगाई का मुख्य कारण ये भ्रष्टाचार ही है। यूथ अगेन्स्ट करप्शन की इस विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में युवा, बुद्धिजीवी एवं महिलाएं शामिल थीं जिन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया।

इसी दिन यमुनापार में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि यूथ अगेन्स्ट करप्शन के राष्ट्रीय संयोजक सुनील बंसल ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि टू-जी में हुए घोटाले से देश को १,७६,००० करोड रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए उन्होंने केन्द्र की वर्तमान सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं और वर्तमान सरकार अपने मंत्रियों को बचाने के कार्य में लगी है। अभी तक जो भी गिरफ्तारी हुई वह सरकार की वजह से नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता के कारण हुई है। श्री बंसल ने युवाओं को संगठित होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सायं कार्यवाह रोशन लाल, डूसू के पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी ,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक मदन प्रसाद महतो ने भी गोष्ठी को संबोधित किया। मंच का संचालन श्री संजय स्वामी ने किया।

वहीं, दिल्ली के मधुबन चौक स्थित सभागार में आयोजित यूथ अगेन्स्ट करप्शन की संगोष्ठी में पंजाब केसरी के मुख्य उपसंपादक श्री हरीश चोपड़ा ने कहा कि हमारे देश में जिस भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। उन्होंने सम्बोधन की शुरुआत रामधारी सिंह 'दिनकर' की पंक्ति- ''रिपू नहीं अन्याय हमें मारेगा, अपने ही घर में स्वदेश फिर हारेगा'' से की। श्री हरीश ने कहा कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण राजनीति का अपराधीकरण और जोड़-तोड़ की राजनीति है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण चुनावी तंत्र की व्यवस्था है। चुनाव में खर्च बढ़ रहा है। राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये खर्च करता है और जीतने के बाद तीन करोड़ की डील करता है। उनके अनुसार युवाओं में राष्ट्रवाद की कमी नहीं है सिर्फ आवश्यकता है उन्हें एक दिशा देने और संगठित करने की। उन्होंने युवाओं को गरिमामय इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

गोष्ठी में पधारे हुए कवियों श्री अनिल अग्रवंशी और श्री गजेन्द्र सोलंकी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से लोगों का दिल जीत लिया। गजेन्द्र सोलंकी ने अपनी कविता ''बचा लो अपना हिन्दुस्तान, जगे नहीं तो मिट जायेगी जग में अपनी शान'' का पाठ किया।

इस दौरान गोष्ठी में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया कि वे न तो भ्रष्टाचार करेंगे और न ही भ्रष्टाचार सहेंगे। गोष्ठी का समापन वंदेमातरम गीत के साथ हुआ।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी है व्यापक लड़ाई

सुबील आंबेकर

गत कुछ महीनों से भारत के लोग विशेषकर छात्र-युवा अपनी नागरिक जिम्मेदारी को लगातार निभाते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवश्यक संघर्ष को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं।

मुझे याद है कि गत दिसम्बर (२०१०) में बंगलूरु में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर के लगभग सभी जिलों के विभिन्न परिसरों से छात्र आये थे। वे खुलकर कह रहे थे कि सभी परिसरों में भ्रष्टाचार की घटनाओं को लेकर काफी गुस्सा है। सभी ने कहा उनके शहरों एवं गांवों में लोग अब भ्रष्टाचार से केवल व्यथित होने की जगह इसे मिटाने हेतु कुछ करना चाहते हैं। मैं आपातकाल के कुछ आंदोलनकारियों से मिला। उन्होंने भी कहा यह गुस्से की लहर आपातकाल के पूर्व चली लहर से भी अधिक तीव्र है। वैसे भ्रष्टाचार से लोग तंग तो काफी समय से थे। परंतु राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला, २-जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला जैसे घोटालों से लोगों का आक्रोश सतह पर आ गया। इन घोटालों को दबाने का प्रयास प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार ने बेशर्मी से किया। इससे लोगों का गुस्सा कई गुना बढ़ गया। तब से ही सामान्य लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की मशाल अपने हाथ में ले ली है।

विपक्ष द्वारा संसद में उठाई गयी आवाज व उच्चतम न्यायालय के कड़े रवैये के परिणामस्वरूप लगातार भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसना प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात ए. राजा, सुरेश कलमाड़ी तथा कई अन्य का तिहाड़ जेल पहुंचना प्रारंभ हो गया। प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष सहभाग से मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में हुई भ्रष्टाचारी की नियुक्ति तथा भ्रष्ट तरीके से हुआ एस-बैण्ड सौदा अंततः रद्द कर दिया गया। इन घटनाओं ने आम आदमी का यह विश्वास बढ़ा दिया कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसना संभव है। सितंबर २०१० में राष्ट्रमण्डल खेलों की अव्यवस्था को उजागर करने से लेकर सामान्यतः समाचार माध्यमों ने भ्रष्टाचार के प्रकरणों को जनता में उजागर करने का काफी ठोस कार्य लगातार जारी रखा है। यह भी आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ।

दबाव में सरकार

परिणामस्वरूप जनवरी २०११ से लगातार सभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों में जनता का सहभाग बढ़ने लगा। विद्यार्थी परिषद के फरवरी में हुए देशव्यापी अनशन या संसद मार्च (०४ मार्च) को छात्रों ने काफी समर्थन दिया। विद्यार्थी परिषद ने पहले ही कहा है कि इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री एवं सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। बाद में बाबा रामदेव ने विदेशी बैंकों में सड़ रहे भारतीयों के कालेधन को वापस लाने का मुद्दा उठाया। उनके समर्थन में बढ़ते जनसहभाग से सरकार काफी दबाव में आयी। दूसरी तरफ अण्णा हजारे द्वारा उठाये गये जनलोकपाल के मुद्दे पर भारी जन समर्थन उमड़ने लगा। लोगों को यह विश्वास हो गया कि कड़े लोकपाल कानून से भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी तथा रोजमर्रा के जीवन में काफी हद तक भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी सहित पूरी सरकार ईमानदारी से बेईमानों की अपनी फौज को बचाने हेतु सभी तरह के हथकंडे अपनाने पर अभी भी उतारू है। अप्रैल में हुए अण्णा हजारे के अनशन के पश्चात लोकपाल हेतु संयुक्त ड्राफ्ट समिति बनायी गयी। परंतु निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया। बाबा रामदेव ने ४ जून से कालेधन पर रामलीला मैदान में अनशन प्रारंभ किया, लेकिन सरकार ने पुलिस द्वारा उसे तानाशाहों की तरह कुचलने का घिनौना प्रयास किया। इस पृष्ठभूमि में जब दोबारा अण्णा हजारे जन लोकपाल कानून को लेकर अनशन पर बैठने निकले तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु लोगों ने पुराने

अनुभवों को देखते हुए सरकार की चाल को नाकाम करने का निश्चय कर लिया व लोग स्वतः सड़कों पर निकले। परिणामस्वरूप दबाव बढ़ता गया। अब स्थायी समिति में सरकारी लोकपाल के साथ जन लोकपाल सहित सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय सभी दलों द्वारा संसद में व्यक्त होने के पश्चात ही उनका अनशन टूटा। पूरे देश में उत्साह की लहर उठी। हजारों लोगों के सतत् तेरह दिन देशव्यापी सक्रिय सहभाग के कारण श्री अण्णा हजारे का रामलीला मैदान का यह अनशन (१६-२८ अगस्त) ऐतिहासिक बन गया।

वस्तुनिष्ठ विश्लेषण

अब इसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण सभी आंदोलनकारी संस्थाएं, सामान्य जनता, सरकार, मीडिया एवं बुद्धिजीवियों सभी के लिए नितांत आवश्यक है।

आजादी का आंदोलन काफी व्यापक एवं लंबा था। उसमें देश की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत भावना जुड़ी थी एवं स्वयं महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे। परंतु स्वतंत्र भारत में वे अपेक्षित व्यवस्थाओं को लागू करने की स्थिति में नहीं थे। यही बात आपातकाल के पश्चात जेपी जैसे व्यक्तित्व के साथ अनुभव में आयी। इसलिए अब यह मान लेना स्वप्नदर्शिता होगी कि जल्द ही सब कुछ बदल जायेगा। यह बदलना संभव होगा जन आंदोलनों से ही, लेकिन पुराने अनुभवों से कुछ सबक लेकर।

जैसे आजकल कुछ लोग भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की तुलना अरब देशों में हुई क्रांति से करते हैं। लेकिन उन देशों में २५-३० वर्षों से चल रही तानाशाही से मुकाबला था, जहां लोगों के सारे लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त होकर, उन्हें दमन तथा बंदूकों का सामना करना पड़ रहा था। वहां की कुंठाएं हमसे अलग थीं, जरूरतें भी अलग, उपाय भी अलग थे।

हमें अपने लोकतंत्र को, कानूनों को जन दबावों से ठीक रास्ते पर लाना है। इसलिए लोगों में जागृतिए फिर उनकी सतर्कता एवं सक्रियता और उस आधार पर खड़ा जन-आंदोलन हमारी आवश्यकता है। बीते दिनों के आंदोलन एवं लगभग एक वर्ष से संसद में तथा मीडिया में चल रही बहस, यह सभी अपेक्षित परिवर्तन के वाहक बने हैं।

भ्रष्टाचार का मायावी रूप

भ्रष्टाचार के कई स्वरूप हैं तथा वह कई मायावी रूपों में हर जगह फैला है। इसलिए सक्षम लोकपाल महत्वपूर्ण होने पर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा उसकी पहल पर गठित यूथ अगेंस्ट करप्शन (भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा) ने १४ मुद्दों का (पहले १३ मुद्दे थे) जनादेश ही तैयार किया है। महत्वपूर्ण मुद्दा है काला धन। विदेशी बैंकों में कई लाख करोड़ रुपए भारतीयों के गुप्त खातों में जमा है, तो दूसरी तरफ देश में भी

लगभग १३ अरब रुपये बैंकों में १० वर्ष से लावारिस पड़े हैं। फिर बड़ी-बड़ी कम्पनियों, सरकारी अफसरों एवं राजनेताओं के बीच घूम रहा कालाधन भी विशालकाय है। यह सब इस देश के आम लोगों के विकास हेतु वसूल करना भी राष्ट्रीय कर्तव्य है तथा इस लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव सुधारों को २०१४ के आम चुनावों के पहले लागू कराना होगा। सामान्य व्यक्ति का पुलिस, न्यायालय, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल तथा किसी भी सरकारी कार्यालय से जब भी संबंध आता है, उसे भारी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। उसे इस झंझट से छुटकारा देने हेतु इस तंत्र में कई सुधार तथा आधुनिकीकरण आवश्यक है। यह व्यवस्था परिवर्तन हमारी भारत की आत्मा एवं आवश्यकता के अनुरूप करने हेतु जन दबाव समय की मांग है।

प्रस्तुत जनलोकपाल में भी कुछ बातें जरूर विचारणीय हैं। जैसे सक्षम लोकपाल में प्रधानमंत्री शामिल हो, लेकिन उन्हें मुक्त रूप से सकारात्मक कार्य करने हेतु उनके पर्याप्त अधिकारों की रक्षा भी हो। वैसे ही न्याय व्यवस्था को इस कानून के दायरे से बाहर ही रखा जाए ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। अर्थात उसे भ्रष्टाचार मुक्त रखने हेतु स्वतंत्र कठोर कानून जरूरी है। जनलोकपाल में गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अनुदान लेने वाली संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को भी मुक्त रखा गया है। यह सरासर गलत होगा। आजकल भ्रष्टाचार से सरकारी तंत्र की कई नीतियां प्रभावित करने का कार्य इन दोनों द्वारा भारी मात्रा में हो रहा है। इस हेतु निजी क्षेत्र (कार्पोरेट कंपनियां) एवं वे गैर सरकारी संगठन, जो सरकारी अनुदान अथवा विदेशों से दान लेते है, उन्हें भी इस दायरें में शामिल करते हुए घूस संबंधी कानून में भी संशोधन किया जाए।

वैचारिक छुआछूत त्यागो

भ्रष्टाचार की व्यापकता एवं भयावहता देखते हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को व्यापक मुद्दों पर चलाते हुए भ्रष्टाचारियों को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। इसलिए आंदोलन के सभी नेताओं एवं संगठनों को व्यापक एवं खुला दृष्टिकोण रखना होगा। सबसे पहली बात आंदोलन तभी प्रभावी होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी होगी। इसलिए वैचारिक छुआछूत को छोड़कर चलना होगा। जनता अण्णा हजारे, बाबा रामदेव या विद्यार्थी परिषद तथा यूथ अगेन्स्ट करप्शन जैसे सभी को एक साथ देखना चाहती है। दूसरी बात यह कि सभी राजनेताओं को आरोपित करना आजकल फैशन बन गया है, या हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं यह दूसरा फैशन है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल में चोर हैए तो उसे चोर कहना पड़ेगा। आंदोलन से विपक्षी दलों का भी शुद्धिकरण होगा लेकिन उन्हें नकार कर हम भ्रष्ट सत्ता को ही मदद करेंगे। यह भी ध्यान में रखना होगा।

केन्द्र स्तर का भ्रष्टाचार भी अंततः हमारे सामान्य लोगों के जीवन में काफी प्रभाव डालता है, यह हमें समझना होगा तथा आन्दोलन के नेताओं को भी सामान्य लोगों के रोजमर्रा के भ्रष्टाचार के संकट को समझना होगा। इसलिए भविष्य में यह आंदोलन दोनों स्तर पर बराबरी से चलाना होगा।

महात्मा गांधी ने १९०९ में इंडिया हाउस में विजयादशमी के उत्सव में कहा था कि भारत में श्रीराम, सीता, भरत, लक्ष्मण की उदात्त प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति उत्पन्न हो जाएं तो देश पुनः समृद्ध होगा एवं उसे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आज भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार करने हेतु अपने व्यक्तित्व को हमें उपरोक्त अपेक्षानुसार ढालना होगा।

(लेखक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है)

शिक्षा का व्यावसायीकरण

रुपम गौर

आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर ओर लाभ कमाने की प्रवृत्ति छाई है, चाहे वस्तु हो या सेवा, उसके विक्रय के माध्यम से अधिक-अधिक लाभ कमाना प्रत्येक व्यापारी का मुख्य उद्देश्य हो गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का क्षेत्र भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। आज शिक्षा को भी व्यापार के ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा है जिसमें कि उद्योग धंधों में शामिल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भांति ही वस्तुओं या सेवाओं के विक्रय के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृति बढ़ती जा रही है।

तीव्रगति से बढ़ते वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, स्तरीकरण, बाजारवाद जैसी अनेक चुनौतियों को सामने लाकर खड़ा किया है। आज हमारे देश में अन्य देशों के विद्यार्थियों को अपने यहां की शिक्षण संस्थाओं में मोटी रकम लेकर प्रवेश देना, अपने देश की शैक्षणिक तकनीकों, ज्ञान, पाठ्यक्रमों को अन्य देशों में बेचना, अपने देश के शिक्षकों तथा दूसरे शिक्षाविद् लोगों को दूसरे देशों में शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भेजना आदि का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बाजारवाद तीव्र गति लेता जा रहा है। आधुनिक समय में शिक्षा के प्रचार-प्रसार और हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच की बातें तो बहुत की जा रही हैं। प्राचीन समय में जहां शिक्षा का मूल्य लगाना भी पाप समझा जाता था, वहीं आज शिक्षा एक व्यापारिक वस्तु बन गई है।

अनेक शिक्षाविद रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, महर्षि अरविन्द आदि ने शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझाते हुए बताया है कि शिक्षा मानव को मुक्ति का रास्ता दिखलाती है। शिक्षा मानव को बौद्धिक और भावात्मक रूप से इतना मजबूत और दृष्टिवान बनाती है कि वह स्वयं ही आगे बढ़ने का रास्ताए ज्ञान सृजन का मार्ग और ज्ञान के सहारे अपने विकास का रास्ता ढूंढ़ने के योग्य हो जाता है। जबकि आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रनिर्माण व व्यक्तिगत निर्माण की बजाय अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। आज की शिक्षा बच्चों को नैतिकता, धर्म, सामाजिक मूल्यों के प्रति आदर आदि के बजाय अधिक से अधिक वेतन कमाने योग्य बनाने पर सुझाव देती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना अर्थशास्त्र के रेट ऑफ रिटर्नस के सिद्धांत से की जा सकती है। जिस प्रकार व्यापार में उत्पादन कार्यों में लगाई गई लागत से अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति की भावना होती है, ठीक वैसे ही शैक्षणिक कार्यों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

आज की शिक्षा-प्रणाली पूर्णतः व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित होती चली जा रही है। शिक्षा का व्यवसाय करने वालों के लिए शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जिसके ज्ञान का उपयोग अध्यापन कार्य, पाठ्यसामग्री का निर्माण आदि में किया जाता है। जिनके विक्रय मूल्य के रूप में उसे मोटी धनराशि अदा की जाती है। इस प्रणाली का प्रमुख तत्व विद्यार्थी एक उपभोक्ता मात्र होता है जिसे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा यह प्रलोभन या यकीन दिलाया जाता है कि हमारे संस्थान में उसे दूसरे संस्थान की अपेक्षा बेहतर उत्पाद अर्थात शिक्षा मिलेगी, इस हेतु वे विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभनों का सहारा लेते हैं। आज प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, विज्ञापनों के माध्यम से अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के प्रचार-प्रसार करते हैं। हर इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रबंधकीय संस्थाओं के विज्ञापनों में यह बिंदु मुख्य रूप से होता है कि हमारे यहां साल भर से अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कैंपस सलेक्शन कराया जाता है जिनका सालाना पैकेज लाखों की राशि में होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया किसी वस्तु या सेवा के व्यापारी की भांति प्रतीत होती है। आज की शिक्षा का मुख्य

उद्देश्य नैतिक गुणों का विकास करना न होकर उच्च स्तर का वेतन प्राप्त कराना होता है।

शिक्षा के बढ़ते हुए व्यापार का एक प्रमुख कारण तीव्रगति से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ निजीकरण है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज में स्तरीकरण, शिक्षा में असमानता जैसी कई विकट समस्याओं को जन्म दिया है। आज संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में निजी शिक्षण संस्थाओं का एक जाल सा फैला हुआ है। जिसमें अनेक प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, संस्थान शामिल हैं जिसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं पालकों को अपने में जकड़ रखा है। निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रचार.प्रसार व साधन संपन्न वर्ग के प्रभाव से प्रभावित हो समान्य जन अपने बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिलाना अपना स्टेट्स सिंबल मानने लगे हैं जो समाज में एक प्रकार से वर्ग विभेद को जन्म देता है। पूंजीपति व साधन संपन्न वर्ग के लिए तो अपने बच्चों को इन मोटी फीस वसूल करने वाले स्कूलों में पढ़ाना आसान होता है। आय में से अन्य खर्चों की कटौती कर इन विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। बदले में ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का लालच देकर भवन निर्माणए पाठ्य-सामग्री, स्कूल ड्रेस, डायरी, जूत्ते-मोजे आदि के नाम पर मनमाना पैसा वसूल करते हैं।

आज शिक्षा का व्यापार करने वाली ये शिक्षण संस्थाएं बड़े.बड़े शापिंग महल व पांच सितारा होटल्स की तरह नजर आती हैं जो अपने विद्यार्थियों को वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, टीवी,

कंप्यूटर्स, इंटरनेट आदि तकनीकी के आधुनिक माध्यमों से अध्यापन कराने, गतिविधियों के नाम पर बड़े-बड़े स्विमिंग पूल खेल के मैदान आदि उपलब्ध कराते हैं, जिन तक सिर्फ उच्च साधन संपन्न, धनी वर्ग के बच्चों का ही प्रवेश सीमित होता है, क्योंकि उपर्युक्त सेवाओं के लिए वसूल की जाने वाली मोटी रकम अदा करना एक सामान्य अभिभावक की पहुंच के बाहर होता है। इसके अलावा दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी होता है जिसके पास बैठने के लिए टेबल कुर्सी तो दूर की बात है, टाट पट्टियां भी उपलब्ध नहीं होती हैं। विद्यालय के नाम पर एक जर्जर भवन उपलब्ध होता है। विद्यार्थियों का एक वर्ग इसी हालत में अभाव वाली शिक्षा पाने को मजबूर होता है। यह स्थिति समाज में वर्ग-विभेद को बनाने तथा उसे भविष्य में आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न करती है।

एक ओर तो हम हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा में समानता लाने की बात करते हैं। वहीं शिक्षा का यह बढ़ता हुआ व्यवसायीकरण तथा निजीकरण बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा में असमानता लाता है। एक पांच सितारा स्कूल से पढ़कर निकला बच्चा तथा एक अन्य सामान्य सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा दोनों में ही तुलनात्मक रूप से अनेक मनोवैज्ञानिक अंतर नजर आते हैं।

ऐसी अनेक परिस्थियां तथा प्रश्न हैं जो शिक्षा के व्यवसायीकरण व निजीकरण ने हमारे सम्मुख ला खड़े किए हैं तथा भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियों की ओर इंगित करते हैं।

पाकिस्तान से आए हिन्दुओं ने कहा

मर जाएंगे, पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे

वह समय था १५ सितम्बर की सुबह के लगभग ११ बजे का और जगह थी दिल्ली में यमुना किनारे मजनूं का टीला स्थित डेरा बाबा धुनीदास। खुले आसमान के नीचे जमीन पर पतली सी चादर बिछाकर कुछ महिलाएं लेटी हुइ थीं, कुछ अपने बच्चों को नहला रही थीं, तो कुछ बरसात में गीली हो चुकी लकड़ियों को जलाने का प्रयास कर रही थीं ताकि खाना पकाया जा सके। भूख से बिलबिलाते नंग-धड़ंग कुछ बच्चे कभी उस मिट्टी के चूल्हे के पास जा रहे थे जिससे केवल धुआं निकल रहा था। ये बच्च अपनी-अपनी मां के पास जाकर खाने की मांग कर रहे थे। किंतु उन माताओं के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था।

ऐसे लगभग ६०० महिला-पुरुष और बच्चे ६ सितम्बर को पाकिस्तान से भारत आए हैं। इनमें से ११४ दिल्ली में हैं। ये सभी हिन्दू हैं और पाकिस्तान में कट्टरवादियों के बर्बर अत्याचारों को वर्षों से सहते रहे हैं। अपनी बहू-बेटियों की इज्जत की रक्षा, जान की सुरक्षा और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए ये लोग वर्षों से भारत आने के लिए वीजा मांग रहे थे। पिछले दिनों इन लोगों को बमुश्किल पर्यटक वीजा मिला और ये भारत आ गए। इन गरीब हिन्दुओं के पास न तो खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए वस्त्र। इन सबके लिए खाने, रहने आदि की व्यवस्था स्थानीय हिन्दुओं की मदद से बाबा डेरा धुनीदास ने की है। सामाजिक संस्था सेवा भारती ने भी इनके लिए खाद्य सामग्री और दवा आदि भेजी। कुछ अन्य सेवाभावी बन्धु भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल इन्हें ठहरने और खाने कीए चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ वीजा अवधि की, क्योंकि वीजा केवल ३५ दिन के लिए है। इसलिए ये सभी रात-दिन इस उधेड़बुन में लगे हैं कि वीजा अवधि कैसे बढ़ाई जाए। वीजा अवधि क्यों बढ़ाना चाहते हैं, भारत में क्यों रहना चाहते हैं, इसका जवाब ४१ वर्षीय गंगाराम ने दिया। 'पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ पशुओं से बदतर व्यवहार किया जाता है। वहां की अवाम हिन्दुओं के

साथ पग-पग पर दुर्व्यवहार करती है। फरियाद लेकर पुलिस. प्रशासन के पास जाते हैं तो उलटे हिन्दुओं को ही मारा-पीटा जाता है। हमारी बहू-बेटी अकेली घर से निकल नहीं पाती हैं। बच्चों को स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। हम लोगों से खेतों पर दिन-रात काम करवाया जाता है। किंतु जायज मजदूरी नहीं दी जाती है। मांगने पर पिटाई करते हैं। घर और मंदिर में आग लगा देते हैं। इतनी बुरी हालत में हिन्दू वहां हिन्दू के नाते नहीं रह सकता। हम लोग पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। यदि भारत सरकार हमें यहां नहीं रखना चाहती है, तो गोली मार दे। हम लोग मरना पसंद करेंगे, पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे।'

गंगाराम न्यू हला, जिला-मटियारी, सिंध के रहने वाले हैं। इनके परिवार में कुल ४६ लोग हैं। घर के सभी पुरुष सदस्य, पाकिस्तान में मजदूरी करते थे। वहां स्त्रियां डर से घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। ये लोग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि उन्हें इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। इन्हें लगता है कि भारत में हिन्दू के नाते वे रह सकते हैं, और खुली हवा में सांस ले सकते हैं।

जब गंगाराम अपनी आपबीती बता रहे थे तब मिट्ठूमल्ल गुमसुम एक किनारे बैठे थे। कुछ

पूछा तो उनकी आंखें डबडबा गईं। मिट्ठूमल्ल के साथ जो हुआ है उसे जानकर हर किसी का जिगर चीत्कार कर उठेगा। मिट्ठूमल्ल ने कहा, जिला सांघड़ के जामगोठ गांव में मेरा बड़ा सा घर था और २१ सदस्यीय परिवार के गुजारे के लिए जमीन भी थी। किंतु तीन साल पहले गांव के ही कट्टरवादियों ने हम पर एक झूठा आरोप लगाया और घर जला दिया। जमीन पर भी कब्जा कर लिया। जान बचाकर हम लोग गांव से निकल गए और दूर के एक जंगल में छुपकर रहे। हम लोगों के पास न तो पैसा था और न ही खाने के लिए एक दाना। ऐसे हालात में जंगल में कब तक रहते। फिर भी भूखे-प्यासे हम लोग वहां कई दिन रहे। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो अपने रिश्तेदारों के यहां गए। रिश्तेदारों ने ही मुकदमा करने को कहा। पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब हमारा घर किस हालत में है, यह भी नहीं पता, क्योंकि फिर हम लोग कभी गांव नहीं लौट पाए। तीन साल का समय हम लोगों ने जंगल, सड़क के किनारे या किसी रिश्तेदार के यहां बिताया है। कुछ हिन्दुओं ने ही हम लोगों का वीजा बनवाया और अब हम लोग भारत आ चुके हैं। भारत सरकार से गुजारिश है कि वह हमें यहां शरण दे।

हैदराबाद (सिंध) के अर्जुन दास अपने परिवार के ११ सदस्यों के साथ आए हैं। कहते हैं, 'पाकिस्तान में हिन्दुओं को सिर्फ खेतिहर मजदूर बनाकर रखा जाता है। मजदूरी भी इतनी कम दी जाती है कि अकेले आदमी का भी गुजारा नहीं होता है। कुछ कहने पर कहा जाता है कि मुसलमान बन जाओ हर चीज मिलेगी। पाकिस्तान की कुल २५ करोड़ आबादी में १ प्रतिशत भी हिन्दू नहीं रह गए हैं। हिन्दुओं को जबर्दस्ती इस्लाम कबूलवाया जाता है। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। हम जैसे लोग किसी भी सूरत में अपने पूर्वजों के सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़कर यहां आए हैं। हिन्दुओं को सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाता है। एकाध हिन्दू किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहा हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। सेना और पुलिस बल में तो हिन्दुओं को लिया ही नहीं जाता है।'

सिंध के हाला शहर से आए रामलीला कहते हैं, 'पाकिस्तान में हिन्दुओं को खुलकर सांस भी नहीं लेने दी जाती है। पड़ोसी मुस्लिम बहुत ही बारीकी से हिन्दुओं पर नजर रखते हैं। किसी हिन्दू त्योहार के आने से पहले ही चेतावनियां मिलने लगती हैं। चाहे होली, दीवाली, रामनवमी या कोई अन्य त्योहार हो, कहा जाता है जो कुछ करो घर के अंदर करो। इबादत की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। शंख, घंटी आदि बजाना सख्त मना है। त्योहारों या अन्य किसी दिन हिन्दू जब मंदिर जाते हैं, तो मंदिर के बाहर मुसलमान खड़े रहते हैं और कहते हैं मंदिर क्यों जाते हो, मस्जिद जाओ। उनकी बात नहीं मानने पर हिन्दुओं पर हमले किए जाते हैं। घरों में आग लगा दी जाती है।'

हाला शहर के ही चंदर राय की उम्र सिर्फ १८ साल है। वे मोटर मैकेनिक हैं। कहते हैं, 'लोग गाड़ी ठीक करवाकर मुझे पैसे नहीं देते थे। कहते थे मुस्लिम बन जाओगे तो तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। किंतु मैं अपनी जान दे सकता हूं, धर्म नहीं। पाकिस्तान में हिन्दुओं का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैंने वहां शादी भी नहीं की। सोचा कि जब यहां मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो फिर शादी करके अपने बच्चों को इस नरक में क्यों लाऊं। पाकिस्तान में हिन्दू पैदा हो तो मुसीबत और मर जाए तो और बड़ी मुसीबत। यदि कोइ हिन्दू मर जाता है तो अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता है। मुसलमान कहते हैं मुर्दे को जलाने से बदबू आती है, इसलिए उसे दफना दो। यही वजह है कि अपने किसी रिश्तेदार के मरने पर हिन्दू रो भी नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि रोए तो पड़ोसी मुसलमान को पता लग जाएगा और फिर वे उसे दफनाने पर जोर देंगे। हमलोग अपने किसी मृत परिजन का अंतिम संस्कार चोरी-छुपे रात में कहीं सुनसान जगह पर करते हैं। शव को आग लगाने के बाद भाग खड़े होते हैं।'

डेरा बाबा धुनीदास के संचालक राजकुमार कहते हैं पाकिस्तान से आए इन हिन्दुओं की हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने हिन्दू समाज से भी कहा कि हिन्दुओं की सहायता के लिए खुलकर आगे आए। उनके इस आह्वान पर कई लोग इन हिन्दुओं की मदद में लगे हैं।

लोग अब गरीब नहीं रहेंगे

अवनीश सिंह

अब यह स्पष्ट हो गया है कि संप्रग सरकार महंगाई को बेलगाम करके आम जनता का दम निकालने पर तुली हुई है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में ३.१४ रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करके उसने मंशा साफ कर दी है। इस सरकार के राज में पिछले २७ माह में ही १७वीं बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गत जनवरी से लेकर इन साढ़े आठ महीनों में ही ८.४७ रुपये बढ़ाये जा चुके हैं। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल मूल्य में करीब दुगुना तो टैक्स ही वसूला जाता है। सरकार ने पेट्रोल मूल्य को नियंत्रण मुक्त करके पेट्रोलियम कंपनियों के रहमोकरम पर जनता को छोड़ दिया है, यह उसकी संवेदनहीनता को ही दर्शाता है।

वस्तुतः महंगाई की मार केवल पेट्रोल पर ही नहीं है, अभी रसोई गैस की कीमतों में भी मूल्य वृद्धि की सिफारिश की गई है। इस तरह एक और तलवार आम आदमी की रसोई पर लटकी है जो कभी भी उस पर आघात कर सकती है। बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा रुपये की विनिमय दर में गिरावट और डालर की दर में वृद्धि होने से यह मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई थी। लेकिन यह तर्क सैद्धांतिक हो सकता है, व्यावहारिक दृष्टि से तो इस सरकार के शासन में जनता महंगाई की असह्य मार झेल रही है। सरकार कहती है कि भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर विश्व क्षितिज पर उभर रहा है, इसके विपरीत भारत की मुद्रा की ऐसी दुर्दशा कि उसकी कमजोरी के कारण देश की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़े! यह कैसा विरोधाभास है? खाद्य पदार्थों की कीमतें तो जानलेवा साबित हो रही हैं। तेल, घी, चावल, चीनी, गेहूं, दूध, सब्जियां आदि आवश्यक वस्तुएं लगातार आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।

महंगाई दर २ अंकों के करीब है। आम आदमी का जीना मुहाल है। लगातार बढ़ रही कीमतों से हाहाकार मचा है। आखिर इस सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेही है की नहीं? इसने बाजारी शक्तियों को जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। उदार अर्थनीति का क्या अर्थ लगाया जाए कि आर्थिक रूप से आम जनता तो लुटती-पिटती रहे और बाजार निर्बाध मुनाफा कमाता रहे। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को क्या जनता की आवाज नहीं सुननी चाहिए और उसके समाधान के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए? जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो बेबस जनता अपनी ताकत दिखाकर ऐसी सरकार को उलट भी देती है। जनता के प्रति संवेदनहीन बनी संप्रग सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए।

किंतु भारत सरकार की नजर में ये लोग अब गरीब नहीं रहेंगे। अगर सरकार की मनमानी यूं ही चलती रही तो गरीबों को गरीबी उन्मूलन के लिए चल रहीं योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को न तो इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा और न ही सस्ता अनाज। बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) सूची से भी इनके नाम हट जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वाले उस व्यक्ति को गरीब नहीं मानती है, जो प्रतिदिन ३२ रुपये खर्च करता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन २६ रुपये खर्च करने वालों को भी सरकार गरीब की श्रेणी में नहीं रखना चाहती है। गरीबी की यह नई सरकारी परिभाषा योजना आयोग के माध्यम से बाहर आई है। आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं यह परिभाषा तथ्यों पर आधारित है इसलिए बिल्कुल ठीक है। किन्तु अर्थशास्त्री इस परिभाषा को सिरे से नकार रहे हैं। दरअसल भारत सरकार उभरती अर्थव्यवस्था का जो जुमला गढ़ रही है उसमें गरीब और गरीबी कालीन में पैबन्द की तरह नजर आते

हैं, इसलिए सरकार अपनी नाक बचाने के लिए आंकड़ों में गरीबी का खात्मा करने पर तुली है।

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि गरीबी की परिभाषा क्या है? इसके जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में काम करने वाले योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र दाखिल कर कहा कि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति मासिक ६६५ रुपये और कोई ग्रामीण प्रतिमाह ७८१ रुपये खर्च करता है, तो वह गरीब नहीं है। देखा जाये तो आजकल शहरों में ३२ रुपये में तो एक वक्त का भी पौष्टिक खाना नहीं मिलता है। सरकार गरीबों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। सरकार यह मजाक सिर्फ इसलिए कर रही है कि गरीबों के लिए चलाई जा रहीं सरकारी योजनाओं को वह सार्थक सिद्ध करना चाहती है। सरकारी योजनाओं को जबरदस्ती कामयाब बताने के लिए इस सरकार ने अर्जुन सेनगुप्ता आयोग की उस रपट को भी झुठला दिया है, जिसमें कहा गया है कि देश में ७५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो रोजाना २० रुपये या उससे कम पर गुजारा करने को मजबूर हैं। यहां सवाल उठता है कि लोग अर्जुन सेनगुप्ता आयोग की रपट को सही मानें या योजना आयोग की इस नई परिभाषा को?

योजना आयोग यह भी मानता है कि शहर या गांव में रहने वाला एक व्यक्ति क्रमशः ३२ एवं २६ रुपये में खाना तो खा ही लेगा साथ ही साथ उसकी शिक्षा और चिकित्सा का खर्च भी पूरा हो सकता है।

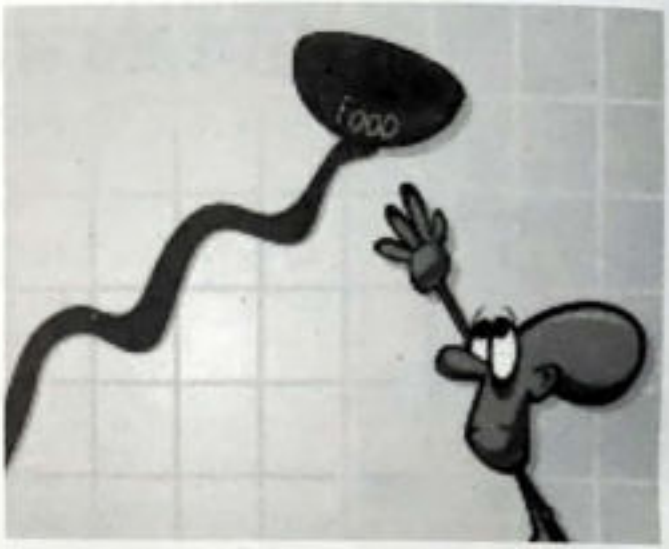

ऐसी बेतुकी दलील देने वाले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया स्वयं औसतन हर रोज ११,३५४ रुपये विदेश यात्रा पर खर्च करते हैं।

जो लोग गरीबी की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, वे लोग दिनभर में सरकारी खर्चे पर करीब १०० रुपये का पानी और लगभग १५० रुपये की चाय या कॉफी पी जाते होंगे। खाने पर कितना खर्च करते होंगे, इसका अंदाजा भी एक आम आदमी को नहीं है। इनके रहने के लिए वातानुकूलित सरकारी कोठी है, चलने के लिए लालबत्ती लगी सरकारी गाड़ी है। देश-विदेश में घूमने के लिए सरकारी खजाना खुला रहता है। ये बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए तुरंत लंदन या न्यूयार्क के लिए उड़ जाएंगे। इनके बच्चे देश-विदेश के महंगे शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। ऐसे लोगों की चल-अचल सम्पत्ति भी सालों-साल बढ़ती जाती है। फिर भी महंगाई की दुहाई देकर अपनी तनख्वाह और भत्ता एक झटके में दुगुने से भी अधिक बढ़ा लेते हैं। और जो वास्तव में गरीब हैं उनके लिए इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में भी ये लोग कहते हैं ३२ रुपये और २६ रुपये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हैं। यह विडम्बना नहीं तो और क्या है। दरअसल यह गरीबों के साथ क्रूर मजाक है। हां, भारत में एक स्थान है जहां ३२ रुपये से भी कम में विविध व्यंजनों भरा भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वह है संसद की केंटीन। जहां देश के नीति-नियंताओं को यह सुविधा मिलती है।

क्या पाकिस्तान कश्मीर में फिर दोहराएगा एक और कारगिल?

नरेन्द्र सहगल

भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में उठ रही देशव्यापी मुखर आवाज को खामोश कर देने, अहिंसावादी सत्याग्रहियों को कुचल डालने और विपक्षी दलों को पछाड़ देने के लिए दिन-रात एक कर रही सरकार को देश की सीमाओं पर बढ़ती जा रही शत्रु देशों की हलचल का कोई ध्यान नहीं है। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त भारत विरोधी गतिविधियों की अनदेखी करके भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी के सामने एक ही राजनीतिक एजेंडा रह गया है कि किसी भी प्रकार से अपने खोए हुए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी झोली में डाल लिया जाए। भारत की यही रणनीति चीन और पाकिस्तान दोनों को उत्साहित करने में मदद कर रही है।

कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति

भारत के साथ मित्रता और वार्तालाप का नाटक करने वाला पाकिस्तान अपने साथ लगती भारतीय सीमा विशेषतया जम्मू-कश्मीर की सीमा पर एक दूसरा कारगिल रचने की तैयारियां कर रहा है। इस बार पाकिस्तान के सेनाधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर स्थित जम्मू.कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के फरकियान क्षेत्र को चुना है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारतीय सेना तो सतर्क है परंतु भारत सरकार की कमजोर रणनीतिक इच्छाशक्ति सेना का मनोबल तोड़ रही है।

उल्लेखनीय है कि गत ३० जुलाई की रात को पाकिस्तान के रेंजरों (सीमा सुरक्षाकर्मी) ने भारत की सीमा पर उस समय अचानक गोलीबारी प्रारंभ कर दी थी जब पाकिस्तान की विदेशमंत्री हिना रब्बानी खार नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से बात करने के साथ-साथ भारत के विदेश मंत्री से हाथ मिला रही थीं। इधर वार्तालाप और उधर गोलीबारी, यही पाकिस्तान की भारत केन्द्रित विदेश नीति का आधार है जिस पर खड़े होकर पाकिस्तान भारत की सुरक्षा व अखंडता को न केवल चुनौती दे रहा है, अपितु अपनी भावी सैनिक कारगुजारियों का संकेत भी दे रहा है। न जाने क्यों हमारे देश की सरकार इस विषय पर मौन रखे हुए है जबकि हमारी फौज पूरी तरह सतर्क है।

भारतीय सैनिकों के सिर काटे

गत जुलाई के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान के साथ लगती जम्मू-कश्मीर की सीमा पर जो सैन्य हलचलें हुई हैं वे रोंगटे खड़े करने वाली हैं। पाकिस्तान के सैनिकों ने दो भारतीय सैनिकों के सिर काट लिए। इतना ही नहीं वे इन सिरों को अपने साथ भी ले गए। भारत की सीमा के अंदर घुसकर इस प्रकार दुस्साहस करने की घटना का किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। यह भारत की चाकचौबंद सुरक्षा-व्यवस्था पर एक गहरा सवालिया निशान है और साथ में रक्षा मंत्रालय सहित पूरी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने वाला संवेदनशील मुद्दा भी।

इस सनसनीखेज समाचार को दैनिक जागरण ने अपने सात जुलाई के अंक में प्रथम पृष्ठ पर इस तरह दिया है- बीती तीस जुलाई को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित फरकियान गली में जो घुसपैठ हुई थी, वह सामान्य नहीं थी। उसमें आतंकियों के दल के साथ पाकिस्तानी सेना का कमांडो दस्ता भी था। इन लोगों ने वहां टेंपल पोस्ट के आगे नाका लगाने जा रहे जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। हालांकि भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पाकिस्तानी हमलावरों और घुसपैठियों को खदेड़ दिया परंतु वे दो भारतीय सैनिकों के सिर काटकर अपने साथ ले जाने में सफल हो गए।

घुसपैठियों में शामिल पाक सैनिक

यह दोनों सैनिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हल्द्वानी इलाके के रहने वाले थे। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट के हवलदार जयपाल सिंह

और लांसनायक देवेन्द्र सिंह की शहादत की पुष्टि रक्षा मंत्रालय के श्रीनगर स्थित प्रवक्ता ले.कर्नल जे. एस.बराड़ ने कर दी थी। परंतु उन्होंने इस घटना को घुसपैठ का साधारण हादसा करार दिया। यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है कि भारतीय क्षेत्र में किए गए पाकिस्तानी सेना के इस दुस्साहस को नाकाम करने में भारतीय सैनिक क्यों और कैसे चूक गए?

समाचार के अनुसार दोनों सैन्यकर्मियों के पाकिस्तानियों द्वारा सिर काटे जाने की असलियत तब खुली जब उनका अंतिम संस्कार किया जाने लगा। अधिकारियों ने दोनों जवानों के शव उनके परिवारजनों को यह कर दिखाने से इनकार कर दिया कि आतंकियों ने आरपीजी (राकेट प्रोपैल्ड ग्रेनेड) से उन पर हमले किए थे, जिससे उनके सिर उड़ गए। इस असाधारण घुसपैठ से यह तो स्पष्ट हो ही गया कि पाकिस्तान के सैनिक भी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं।

पाकिस्तान की घुसपैठ रणनीति

प्रायः इसी प्रकार की परिस्थितियां १९९९ में हुए भारत-पाक कारगिल युद्ध के समय भी बनीं थीं। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक सादे वेश में हथियारों के साथ सीमा पार करके कारगिल की पहाड़ियों पर काबिज हो गए थे। इन पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों ने अनेक भारतीय चोटियों, गुफाओं और जंगलों में अपने पक्के बंकर स्थापित कर लिए थे। कई महीनों तक किसी को पता तक नहीं चला था। इन घुसपैठियों द्वारा भारतीय फौजी ठिकानों पर जब हमले शुरू किए गए तब हमारे सैन्य प्रतिकार से भारतीय चोटियों को मुक्त करवाया जा सका।

पाकिस्तान अब फिर पहले से भी ज्यादा बेहतर और ताकतवर ढंग से उसी कारगिल रणनीति के इतिहास को सफलतापूर्वक दोहराने की फिराक में है।

सशस्त्र घुसपैठ की पाकिस्तानी रणनीति एक साथ कई निशानों पर मार करती है। सीमा पर हलचल करके भारतीय सैनिकों को रक्षात्मक कार्रवाई में उलझाए रखना, जम्मू.कश्मीर सहित पूरे देश के बड़े शहरों में हिंसा फैलाना और कश्मीरी युवकों को आतंकी संगठनों में भर्ती करके प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजना। ध्यान देने की बात है कि यह घुसपैठिए कश्मीर घाटी के एक विशेष समुदाय के घरों में ठहरते हैं और बाद में इन्हीं की सहायता से पहाड़ों और जंगलों में अपने गुप्त ठिकाने बना लेते हैं। पाकिस्तान की यह घुसपैठ रणनीति १९६५ के भारत-पाक युद्ध के समय से ही चल रही है।

सुरक्षा पर सवालिया निशान

विचारणीय प्रश्न यह भी है कि पाकिस्तानी रेंजरों की कवरिंग फायर की आड़ में भारतीय क्षेत्रों में घुसने वाले प्रशिक्षित आतंकवादी पकड़ में क्यों नहीं आते? पाकिस्तान के साथ लगती जम्मू-कश्मीर की १२६७ किलोमीटर की सीमा (अंतरराष्ट्रीय सीमा-नियंत्रण सीमा) पूरी तरह सील है। बिजली के करंट वाली कांटेदार तारों का ऊंचा जाल पूरी सीमा पर बिछा हुआ है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल की गश्ती टुकड़ियां २४ घंटे मुस्तैदी से गश्त लगाती हैं। थोड़े-थोड़े अंतराल पर ऊंचे-ऊंचे निगरानी टावर हैं जिन पर अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं। इन टावरों पर तैनात जवान अंधेरे में दूर तक देख सकने वाली दूरबीनों के साथ २४ घंटे तैनात रहते हैं। सेना की चौकियों, बंकरों और मोर्चों पर सशस्त्र जवान सदैव तैयार रहते हैं।

राडार, वायरलैस सिस्टम और आवाज कैद करने वाले यंत्रों को स्वचालित सिग्नल पर दिन-रात सक्रिय रखा जाता है।

एक क्षण के लिए भी न रुकने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अगर पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र में घुसकर दो जवानों को मारकर उनके सिर अपने साथ ले जाते हैं तो इससे बड़ी सुरक्षा की नाकामी और क्या होगी? चिंता का विषय यह भी है कि हमारे सीमा प्रहरियों से आंख बचाकर घुसपैठ करने में सफल होने वाले आतंकी युवक अपने स्थानीय गाइड की सहायता से अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचते हैं। वहां कुछ दिन ठहरने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाकर हिंसक वारदात करते हैं और जो बच जाते हैं वे फिर उन्हीं तौर- तरीकों से वापस पाकिस्तान भाग जाते हैं।

पाक सरकार का पूरा समर्थन

भारत सरकार की लाचारी, अकर्मण्यता, नासमझी और कायरता पर सभी देशभक्त संगठन और लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और उधर पाकिस्तान सरकार और सेना कश्मीर की आजादी के मसले पर अपनी बयानबाजी के साथ अपनी भारत विरोधी हरकतों में भारी इजाफा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के शासकों के वक्तव्य, सीमा पर गोलीबारी, हथियारबंद घुसपैठ और कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थक माहौल बनाया जाना इन चार पायों पर निर्मित पाकिस्तान की रणनीति का स्पष्ट दृश्य गत १४ अगस्त (पाकिस्तान के निर्माण दिवस) को दिखाई दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने अपनी जनता के नाम संदेश देते हुए भारत सहित सारे संसार को अपने असली इरादे बता दिए हैं- 'इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया है। पाकिस्तान कश्मीरियों को निर्बाध रूप से नैतिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक समर्थन देता रहेगा ताकि वे अपना अधिकार प्राप्त कर सकें।'

इस प्रकार के पाकिस्तानी शासकों से यह उम्मीद करना कि वे कश्मीर में हो रही सशस्त्र घुसपैठ को रोकेंगे, कोरी मृगमरीचिका ही होगी।

जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीरियों को समर्थन जारी रखने की घोषणा कर रहे थे, उसी वक्त जम्मू-कश्मीर में कई जिलों में रविवार को पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, कश्तवाड़ के जिस चौगान में सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता दिवस आयोजित होना था, वहीं अलगाववादियों ने पाकिस्तानी झंडे लहराकर अपनी मौजूदगी का अहसास कराया।

ठोस नीति और सख्त कार्रवाई

इसी दिन जम्मू संभाग के साम्बा सीमांत क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर गोले बरसाए। इसी तरह कुपवाड़ा सेक्टर में भी सीमा पार से कई घंटे लगातार गोलीबारी होती रही। गोलीबारी और सशस्त्र घुसपैठ की इस पाकिस्तानी फौजी मुहिम के चलते कश्मीर सहित भारत में व्याप्त आतंकवाद को समाप्त करना असंभव है। यह काम कोरी वार्ताओं से संभव नहीं होगा। वास्तव में भाईचारे की भाषा को पाकिस्तान समझता ही नहीं है।

उसकी नजर में बातचीत करना भारत की कमजोरी और मजबूरी है। भारत-पाक के मध्य हुए चार बड़े युद्धों, आतंकी हादसों और घुसपैठ के बाद भारत द्वारा वार्ता की मेजों पर टेके गए घुटनों से पाकिस्तान ने यही निष्कर्ष निकाला है कि भारत सरकार इस बुजदिली को बरकरार रखेगी और पाकिस्तान के इरादे सफल होते रहेंगे।

अतः वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अपने देश की सुरक्षा, स्वाभिमान एवं अखंडता को बचाने के लिए भारत सरकार को एक ठोस और सख्त रणनीति अपनानी होगी। अन्यथा पाकिस्तानी घुसपैठ जारी रहेगी, आतंकी धमाके होते रहेंगे और देश के बेगुनाह लोग मरते रहेंगे, उजड़ते रहेंगे। अपने देश की सेनाए राजनीतिक-सामाजिक संगठन और जनता तैयार है। गेंद सरकार के पाले में है। यह समय पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचल देने का है। कोताही खतरनाक साबित होगी।

'मध्य प्रदेश छात्रसंघ चुनाव'

अभाविप की ऐतिहासिक विजय

मध्य प्रदेश के छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल ने राज्य के सातों विश्वविद्यालयों सहित अधिकाधिक महाविद्यालयों में जीत सुनिश्चित कर पुनः भगवा परचम लहराया है। विद्यार्थी परिषद ने जहां सातों विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया है वही, दूसरी तरफ २४ अन्य पदों पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाजी मारी है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय- इन्दौर, विक्रम विश्वविद्यालय- उज्जैन एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय- रीवा में परिषद के पैनल ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए सभी पदों पर जीत दर्ज की। इसी क्रम में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय- भोपाल से कुमारी नेहा पवार, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से कुमारी वर्षा शर्मा, विक्रम विश्वविद्यालय से कुमारी आकांक्षा, जीवजी विश्वविद्यालय से मानवेन्द्र सिंह भदौरिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय- जबलपुर से कुमारी मीना ठाकरे, महर्षि पणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय से पवन कुमार नागर एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय- रीवा से कुमारी शिल्पी सोनी विजयी हुईं।

कुल मिलाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल ने राज्य के सातों विश्वविद्यालयों से संबद्ध ५०६ कालेजों में हुए छात्रसंघ चुनावों में ३८६ कालेजों में अध्यक्ष. ३६४ कालेजों में उपाध्यक्ष, ३६८ कालेजों में में सचिव और ३६४ कालेजों में सह-सचिव पदों पर भगवा परचम लहराया है।

ऐतिहासिक जीत पर सभी कार्यकर्ता एवं विद्यार्थियों को बधाई

भोपाल, २६ सितंबर। छात्रसंघ चुनाव में म.प्र.

में अभाविप ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवा परचम लहराया है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न हुए छात्रसंघ चुनावों में अभाविप कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ सहभागिता की तथा अधिकतम पदों पर जीत प्राप्त की है। अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सभी युवा कार्यकर्ताओं की जीत है।

उन्होंने कहा कि अभाविप एक देशभक्त, सेवाभावी, अनुशासित छात्र संगठन है जो हमेशा छात्र हितों के लिये तत्पर रहता है इसी का परिणाम है की आज पुरे म.प्र. के छात्र-छात्राओं ने अभाविप को अपना भरपूर समर्थन दिया है। इससे एक बार फिर सिद्ध हो गया की अभाविप ही छात्र छात्राओं का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता है तथा युवाओं ने तथाकथित यूथ आईकॉन को पूरी तरह नकार दिया है। अभाविप ने हमेशा से ही विद्यार्थियों के हितों हेतु परिणामकारी आंदोलन कर उन्हें समस्याओं से राहत दिलाने का कार्य किया है, इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी बधाई के पात्र है।

अभाविप की प्रदेश मंत्री सुश्री भारती कुम्भारे

ने जानकारी देते हुए बताया कि अभाविप ने पूरे म. प्र. में शानदार जीत दर्ज की है, जिसमें सभी महाविद्यालयों में लगभग ६० प्रतिशत पदाधिकारी अभाविप कार्यकर्ता निर्वाचित हुए हैं। सुश्री भारती ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अभाविप का छात्रसंघ चुनावों में शानदार जीत प्राप्त करना यह दर्शाता है कि आज का युवा पूर्ण रूप से अभाविप के साथ है, तथा अभाविप द्वारा देश में शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में चलाये जा रहे आंदोलनों को युवाओं ने पूरा समर्थन दिया है। साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों का अभाविप में विश्वास और दृढ हुआ है। यह ऐतिहासिक जीत इसी का प्रमाण है।

अभाविप भोपाल महानगर मंत्री रितेश बिरथरे ने बताया कि अभाविप ने भोपाल महानगर में अधिकतम पदों पर जीत प्राप्त की हैं, अभाविप ने भोपाल महानगर में कुल ३२ महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव में भाग लिया जिसमें से २३ महाविद्यालयों में सभी पदों पर जीत प्राप्त की है तथा अन्य महाविद्यालयों में भी अधिकतम पदों पर अभाविप प्रत्याशियों ने जीत प्राप्त की है। जिसमें प्रमुख रूप से नूतन कॉलेज, गीतांजली महाविद्यालय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, स्टेट लॉ कॉलेज, केरियर कॉलेज, विक्रमादित्य कॉलेज, साधु वासवानी कॉलेज, कोपल कॉलेज, तक्षशिला कॉलेज, यूनिक कॉलेज, में सभी पदों पर तथा एम.एल.बी. कॉलेज

में अध्यक्ष व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, एम.ही.एम. कॉलेज में उपाध्यक्ष, हमीदिया कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, भेल कॉलेज में सह-सचिव व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों पर अभाविप प्रत्याक्षियों ने जीत प्राप्त की है।

छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात सायं अभाविप प्रदेश कार्यालय छात्रशक्ति भवन, डिपो चौराहा पर सैकडों कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर ढोल-ढमाकों के साथ आतिशबाजी करते हुए सभी विजयी प्रत्याक्षियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाऐं दी।

भ्रष्टाचार देश की बड़ी समस्या

सुनील कुमार बंसल

आज देश के सामने कई प्रकार की समस्यायें हैं जिनके साथ हम रोजाना जूझ भी रहे हैं व उनके साथ जी भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कौन सी है इसको लेकर समाज में अलग-अलग प्रकार के लोगों के अलग-अलग मत हो सकते हैं। अनुभव ऐसा है कि जो जिस समय जिस समस्या से प्रभावित होता है उसके लिए वह उतनी ही बड़ी समस्या बन जाती हैं।

एक आम आदमी के लिए दो समय का खाना जुटा पाना कठिन है तो उसके लिए मंहगाई समस्या है। बिहार असम और पूर्वोत्तर के प्रान्तों में बढ़ रही बांगलादेशी घुसपैठ उनके लिए बड़ी समस्या है , बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार न मिलना समस्या है, अभिभावकों के लिए शिक्षा का व्यापारीकरण समस्या है, जिन परिवारों के लोग आतंकवाद के कारण से मारे गये उनके लिए आंतकवाद बड़ी समस्या है।

मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या वह है, जिसे लोग समस्या मानना बन्द कर दें और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मान कर जीनें लगें। इस प्रकार देखा जाय तो भ्रष्टाचार आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है जिसे आज आम आदमी एक शिष्टाचार के रूप मे मानता है। आज काम के बदले रिश्वत लेना व देना एक नियम सा बन गया। अब समाज में इसे गलत नहीं समझा जाता बल्कि जो विरोध करता है उसे बेवकूफ या आदर्शवादी कह कर उसका मजाक बनाया जाता है। पहले समाज में रिश्वत लेने वाले को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। लोगों के मन में समाज निन्दा कर डर रहता था। रिश्वत लेता था तो भी घर पर लेकर नहीं आता था, परिवार से छुपा कर उसका उपयोग करता था क्योंकि परिवार में गलत संस्कार पड़ेगा। अब तो वही व्यक्ति रिश्वत यह कहकर मांगने लगा है कि मेरे भी तो बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए भी कुछ चाहिये।

कुछ माह पूर्व तक समाज में सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय भी नहीं था। लोगों ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था कि यह तो होगा ही या ये सब तो आवश्यक है।

भ्रष्टाचार का यह महारोग अभी पनपा है ऐसा नहीं है, मुगलों के समय में भी भ्रष्टाचार था पर वह आटे में नमक की तरह था। अंग्रेज तो भारत को लूटने ही आये थे इसलिये येन-केन-प्रकारेण अंग्रेजों ने तो हमें लूटा ही। पर आजादी के बाद आये प्रजातन्त्र मे यह रूकना चाहिये था पर हुआ उल्टा। देश मे पैदा हुये काले अंग्रेजों ने ही हमें लूटना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार की नाली दिन ब दिन चौड़ी होती गई और अब इसने महासागर का रूप ले लिया। कारण देश में प्रजातन्त्र तो आया पर प्रजा की सुनने वाला कोई तन्त्र नहीं बना। अगर देश का राजनैतिक नेतृत्व भ्रष्ट नहीं होता तो प्रजा भी ईमानदार बनी रहती। इन्हीं राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण पारदर्शी तन्त्र को बनने नहीं दिया उल्टे जनता को भी ईमानदार नहीं रहने दिया।

सन् १९४९ में जीप घोटाले और १९५८ मे प्रताप सिंह केरो से जुडे घोटालों के आरोपित लोगों को राजनैतिक शह मिलना, १९७१ में लगे आरोपों के जबाब में इन्दिरा गांधी द्वारा 'करप्शन इज ग्लोबल फैनोमिना' कहना या राजीव गांधी द्वारा यह मानना कि केन्द्र सरकार से भेजे जाने वाले १०० पैसे में से १५ पैसे आम आदमी के पास पहुंचते हैं, ८५ पैसे भ्रष्ट बिचौलिआ व नेता खा जाते हैं पर उनके द्वारा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करना जैसे मुद्दों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया। स्वाधीनता के बाद जीप घोटाले को घोटालों का बीज कहा जा सकता है।

पिछले छः माह से सीरियल ब्लास्ट की तरह सामने आ रहे घोटालों ने तो सारे रिकार्ड तोड़ दिये

है। केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल स्वीकार करते हुए कहते हैं यह घोटाले ३ लाख करोड़ के नहीं हुए। माना कुल राशि इतनी होगी पर उसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है। इन सबके कारण आज हमारा देश सदमे में हैं, लोगों मे भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश उभरता दिखाई दे रहा है। जैसे चीनी हमले, आपातकाल व बोफोर्स घोटाले के समय दिखाई दिया था। परिणामस्वरूप २ वर्षों में जनता ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया। वर्तमान में तो लग रहा है कि जैसे जगमगाता बल्ब अचानक फ्यूज हो जाता है ऐसा ही केन्द्र सरकार की प्रतिष्ठा के साथ हुआ जो इन सीरियल घोटालों के कारण एकदम पैंदे में बैठ गयी।

प्रारम्भ में लोग कहते थे, ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है, आज कह रहे हैं इतनी भ्रष्ट सरकार के प्रधानमंत्री स्वयं ईमानदार कैसे हो सकते हैं, या कहें तो वे भ्रष्टाचार के प्रमोटर प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे मजबूर हैं, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं, गठबन्धन की सरकार है, कार्यवाही करेंगे तो सरकार ही नहीं रहेगी। वे सत्ता और कुर्सी बचाने के लिये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देत रहे हैं। क्या भारत में इससे पूर्व गठबंधन सरकारें नहीं रही? भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण गठबन्धन सरकारें नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में हुआ करती थी, जिसने ५० वर्ष देश में शासन किया है उस समय जो घोटाले हुए उनके लिए कौनसा गठबन्धन व अन्य पार्टियां जिम्मेदार थी। यह तो एक स्वभाव व विकृति का परिणाम है जो कांग्रेस का एक हिस्सा बन गई है।

इन घोटालों की परते खुलने के बाद अब भारत भ्रष्टाचार में सुपर पावर बन गया है। मुट्ठीभर लोगों की बेइमानी के कारण देश की छवि को धक्का लगा है। दुनिया में भारत की पहचान एक वैचारिक, आध्यात्मिक देश की रही है। हमारे यहां समाज जीवन में अर्थ कभी प्रधान नहीं रहा। इन घोटालों के कारण सारी दुनिया भारत की और हैरानी से देख रही है।

गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया ने दुनियाभर के देशों के भ्रष्टाचार के आंकड़े जारी किये जिसमें भारत में ५४ प्रतिशत लोगों ने माना कि उन्होंने कभी न कभी अपना काम कराने के लिए रिश्वत दी है। यहां पर ८० फीसदी नौकरशाह भ्रष्ट है, ग्लोबल ऐंटी करप्शन डे पर ग्लोबल बैरोमीटर के आधार पर भारत दुनिया का नवां भ्रष्टतम देश है, भारत से आगे ईरान, अफगान, पाकिस्तान जैसे देश हैं।

भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेन-देन मात्र नहीं है यह जिस व्यक्ति के पास अधिकार हैं और वह अपने विवेक के आधार पर उनका दुरूपयोग कर जब किसी को लाभ पहुंचाता है तो वह भ्रष्टाचार है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह भ्रष्टाचार बहुआयामी है इसके कारण कैसे समस्यायें बढ़ती हैं या कैसे समस्याओं की जड़ में यह भ्रष्टाचार है, इस पर विचार करें।

भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति के पास जो पैसा आता है उसका यह क्या उपयोग करें? उसे वह बैंक में जमा नहीं कर सकता, अपने पास ज्यादा समय रख नहीं सकता, कहीं पर निवेश भी नहीं कर सकता तो उस पैसे को खर्च करना उसकी मजबूरी हो जाती है जिसे वह अपनी विलासिता पर खर्च करता है। नया मकान बनायेंगे, मकान के डेकोरेशन पर खर्च करेंगे, सभी जगह आवश्यक न होते हुए एयरकंडीशनर लगायेंगे। मॉल में जाकर ब्रान्डेड कपड़ों व लग्जरी आइटम की शॉपिंग करेगें। नये-नये रेस्टोरेन्ट व होटलों मे जाकर खर्चे करेगें। इसी डिमाण्ड के कारण आज सभी शहरों में मॉल संस्कृति व नये-नये रेस्टोरेन्टों व होटलों की बाढ़ आ गयी है इसमें जाने वाले सभी के पास भ्रष्टाचार का पैसा है, ऐसा भी नहीं है उनकी अपनी मेहनत की कमाई को वो खर्चे कर रहे होगें। पर भ्रष्टाचार से आया पैसा ७५ फीसदी तक विलासिता के साधनों पर ही खर्च होता है। इन लोगों के कारण ही समाज मे एक होड़ लग गई है, सभी अपना जीवन स्तर बढ़ाने में अधिक खर्च कर रहे हैं, पैसा नहीं तो बाजार में ऋण सुविधा उपलब्ध है, सामान्य आदमी का बचत करने का स्वभाव व आदत इस कारण कम हो रही है।

भ्रष्टाचार से आये पैसे को चुनावों में खर्च किया जाता है। पहले उद्योगपति या धनवान लोग चुनाव लड़ने वालों को मदद करते थे, बाद में उनसे अपने काम कराया करते थे। अब तो जिनके पास

पैसा आ गया है वे स्वयं ही चुनाव लड़ने लगे हैं। सभी पार्टियां उनको उम्मीदवार बनाती हैं। अपराधियों के पास भी पैसा आने व राजनैतिक संरक्षण मिलने के कारण वो भी अब विधान सभा व लोक सभा में जनप्रतिनिधि बनकर आ गये हैं। राजनीति का आपराधीकरण हो गया है। गलत तरीके से आ रहे पैसे के कारण पूरी चुनाव प्रणाली भ्रष्ट हो गयी है।

भ्रष्टाचार से आये काले धन को हवाला के माध्यम से विदेशों में भेज देते हैं, यह पैसा या तो वहां के बैंकों में जमा हो जाता है या वहां की किसी कम्पनी में निवेश कर देते हैं। इन्हीं विदेशी कम्पनियों के माध्यम से यह पैसा फिर भारत मे निवेश कर दिया जाता है यानि हमारा ही पैसा भ्रष्टाचार के रूप मे बाहर जाकर वापस अपने ही देश में निवेश हो रहा है। उससे और पैसा बनाते हैं, काले धन को सफेद कर लेते हैं। हमारे पैसे से हमारे देश की इकोनोमी को ये पलीता लगाते रहते हैं। हमारा स्टाक एक्सचेंज हमारे नहीं इन लोगों व इनकी कम्पनियों के कन्ट्रोल में रहता है, अपनी इच्छा से उसे अप-डाउन करते रहते हैं। वायदा बाजार के माध्यम से ज्यादा खरीदारी करते हैं फिर मंहगाई बढ़ती है बाद में मुनाफा कमा कर बेच देते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कोई अमेरिका नहीं, मारीशस है जहां से इस प्रकार की कम्पनियों के माध्यम से यह खेल खेला जाता है।

इस काले धन को विदेशों में भेजने व लेन-देन में अपराधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दुबई, पाकिस्तान में बैठकर दाउद जैसे अपराधी इसी काले धन के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। यानि हमारा देश ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वालों का सहयोगी हो रहा है। यानि भ्रष्टाचार मात्र पैसे का लेन-देन ही नहीं यह सभी समस्याओं के बढ़ने का मूल कारण है जो देश को अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहा है।

स्विटजरलैण्ड बैंकिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन में भारत का नाम सबसे ऊपर है। ६५,२२३ अरब रूपये का काला धन इन बैंको में जमा है। यह राशि भारत के वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार से पाँच गुणा अधिक है। भारत में जो विदेशी कर्ज है उसकी तुलना में यह रकम १३ गुणा ज्यादा है। भारत में अब तक ४६२ अरब डालर की आर्थिक अनियमितताओं या घोटले हुए हैं जिसमे ज्यादातर भ्रष्टाचार और रिश्वत की है। यह तो वह राशि है जो सामने आई है जो भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आये उनको जोड़ने पर तो आंकड़े आश्चर्यजनक हो जायेगें। वर्तमान में ही ३ घोटालों (२-जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कहमनवेल्थ खेल घोटाला और महाराष्ट्र का आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाला) के आंकड़े ही लगभग ३ लाख करोड़ रूपये के हैं।

गणतन्त्र की स्थापना के समय देश के संविधान निर्माताओं को भी यह कल्पना नहीं होगी कि उनके द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था ६० वर्ष के अन्दर ही इतनी नैतिकता विहीन हो जायेगी। देश को चलाने के लिए बनाई जा रही संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भी भ्रष्ट लोगों का कब्जा हो गया।

वर्तमान में तो कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार स्वयं भ्रष्ट लोगो को इन संस्थाओं मे नियुक्त कर रही है, सी.वी.सी. थामस की नियुक्ति इसका एक उदाहरण है। दुनिया का यह पहला उदाहरण होगा जिसमें भ्रष्ट व्यक्ति को ही भ्रष्टाचार जांचने वाली संस्था का प्रमुख बना दिया गया हो। जिस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा हो वो स्वयं क्या भ्रष्टाचारियों पर निगारानी रखेगा। लगता है शायद वर्तमान में उभरकर आये घोटालों को दबाने व भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए थामस को नियुक्त किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट थामस की नियुक्ति पर प्रश्न किया तब भी सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। प्रधानमंत्री ने मजबूरी कहकर पल्ला झाड़ लिया। उनकी मजबूरी समझ में आने लायक है उनका ही कार्मिक मंत्रालय उन्हें गलत जानकारियों दे रहा था। पहले भ्रष्ट को बनाओ, फिर उसे बचाने का प्रयास करो, फिर फंसो तो अपनी मजबूरी कहकर अपनी खाल बचाने का काम सरकार ने इस प्रकरण मे किया है।

बहुचर्चित घोड़ा व्यापारी हसन अली पर कई हजार करोड़ रूपये का टैक्स बकाया था उस पर सरकार को हाथ डालने में एक दशक लग गया। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है? जिस पर करोड़ो रूपये

का टैक्स बकाया है उसे गिरफ्तार करने में परहेज क्यों हो रहा है? क्या वह कानून से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार से पहले सरकार इस घोड़े के व्यापारी की तरफ से घोड़े बेचकर सो रही थी। कौन लोग हैं हसन अली के संरक्षक? जवाब स्पष्ट है जिनके काले धन को हसन अली ने ठिकाने लगाया होगा वो ही सरकार में उसे बचाने की पैरवी कर रहे है।

जब भी इस प्रकार के मामले या घोटाले सामने आते हैं, सत्ता में बैठे लोग वही रटा-रटाया जवाब देते हैं- जांच चल रही है, दोषियों को नहीं छोड़ा जायेगा। जांच चलती रहती है, दोषियों को छोड़ दिया जाता है। चार्जशीट दायर होती है पर आरोप सिद्ध नहीं होते। भ्रष्ट व्यक्ति सुरक्षित छूट जाते है हमेशा की तरह भ्रष्टाचारियों को सुरक्षित रखने की परम्परा का निर्वाह किया जाता रहा है, सता के संरक्षण में प्रभावशाली हमेशा बच जाते हैं। वे शर्म से नहीं शान से समाज में जीते हैं। एक मात्र सी.बी.आई. के पास जांच करने का अधिकार है बाकि सभी के पास सुझाव देने के अधिकार है लेकिन सी.बी.आई. की जांच के बाद भी आज तक एक भी राजनेता को सजा नहीं हुई। भ्रष्टाचार करने वालों पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद हमारे कानून में अधिकतम सजा सात वर्ष की कैद है। कोई भी ए. राजा, मधु कोड़ा हजारों करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार करने के बाद भी कुछ साल के लिए जेल में जाने को तैयार हो जायेगा। हमारे कानून में भ्रष्ट व्यक्ति से बापस वसूली की जाय यह व्यवस्था भी नहीं होने से लगता है ऐसे लोगों को आज कानून का डर ही समाप्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट की कुछ माह की सक्रियता देखकर लगता है सरकार कोर्ट के डण्डे से ही चल रही है। २जी स्पेक्ट्रम, हसन अली, सी.वी.सी., थामस के मुद्दे पर कोर्ट की पहल ने जनता के मन की भ्रांति को दूर करने का काम किया है। आम आदमी के मन में एक-एक बात जो बैठ गयी थी कि इन भ्रष्ट लोगों का कुछ भी नही बिगड़ेगा पर अब कोर्ट के निर्णय से उन्हें सम्बल मिला है। पर लोकतन्त्र में न्यायिक सक्रियता की एक सीमा होनी ही चाहिए नही तो उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे नहीं होगे। वैसे तो लोकतंत्र के दो स्तम्भ विधायिका व कार्यपालिका पर भ्रष्ट होने के आरोप लगते रहे हैं पर आज कई प्रश्न न्यायपालिका व मीडिया पर खड़े होना परेशानी भरा है। यहां पर भी आत्मावलोकन करने की आज आवश्यकता है।

नब्बे के दशक में अर्थव्यवस्था को हम मुक्त करके उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो गये। दुनिया के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिये। इस पर उदारीकरण व वैश्वीकरण का हमारे यहां पड़ने वाले प्रभावों को देखकर उस प्रकार की व्यवस्था व कानूनों पर विचार नही हुआ परिणामतः उदारीकरण के कारण से शेयर घोटाले व प्रतिभूति घोटाले सामने आ गये। लेकिन उदारीकरण से ज्यादा वैश्वीकरण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला।

वैश्वीकरण के दौर में हमारे उपर पड़ रहे प्रभावों के कारण धीरे-धीरे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन ही भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है। यह विचार कि भौतिक विकास से ही आदमी सुखी होगा एक एकांगी विचार है परन्तु वैश्वीकरण में हमारे मानस पर विकास का अर्थ यही हो रहा है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे, मॉल, ब्रान्डेड शॉप्स, एडवान्स टैक्नोलॉजी, कम्प्यूटर व फर्नीचरयुक्त कार्यालय, यही विकास के मानक बन गये हैं। सरकारें इस प्रकार के विकास पर खर्च करके ही खुशहाली लाने का दावा करती हैं, यानि पैसा ही विकास का मानक बन गया है। सरकारी खर्चे के माध्यम से इस विकास में नौकरशाह और राजनेताओं का स्वार्थ है। यहीं से तो हसनको लाभ होना हैं, इसलिए वो भी इसी प्रकार के विकास का हिमायती बना हुआ है।

हमारे यहां भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता के समन्वय से ही मनुष्य सुखी होगा यह विचार रहा है। एक बार स्वामी विवेकानन्द से पूछा गया कि आपके धर्म व संस्कृति में दुनिया का मार्गदर्शन करने की ताकत है फिर आपके देश की ऐसी हालत क्यों हो गयी? तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे देश की ऐसी हालत धर्म के कारण से नहीं बल्कि मेरे देशवासियों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया, इसलिए हुई है।

भ्रष्टाचार के तेज गति से बढ़ने के कारण अगर कानून का प्रभावी नहीं होना है तो नये कानूनों पर विचार करना होगा। सख्त कानून बनाने

पड़ेंगे जो हर स्तर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें। इस दिशा में जन लोकपाल विधेयक एक कदम है जिसे लेकर श्री अन्ना हजारे का प्रभावी आन्दोलन हुआ। बिहार राज्य में बना विशेष न्यायालय कानून भी उदाहरण योग्य है।

श्री नीतिश कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति की घोषणा, सभी मंत्री विधायकों सहित नौकरशाह व निचले स्तर के बाबू तक इस प्रक्रिया का पालन होना एक शुरूआत है। बिहार में ही विशेष न्यायालय कानून के तहत भ्रष्टाचारियों पर तुरन्त कार्यवाही का परिणाम आना प्रारम्भ हो गया है, उदाहरणतः मधेपुरा पंचायत के एक सेवक ने ५८ हजार रूपये का गबन किया तो इस कानून के डर के कारण क्षमा याचना सहित वह राशि उसने कलेक्टर को लौटा दी। दूसरा मोटर वाहन निरीक्षक रघुवंश कुंवर पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाने पर उसकी सम्पत्ति जब्त कर उसके मकान में स्कूल खोल दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार का कानून बनाया है। प्रभावी कानून बनाकर व प्रभावशाली लोगों पर कठोर कार्रवाई करके ही समाज में व्याप्त निराशा को दूर किया जा सकता है।

हमारी सरकार को विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी होगी व भविष्य में कालाधन बाहर न जाये इसके प्रावधान करने होगें। कालाधन जमा करने में ५०० व १००० रूपये के नोटों का बडा महत्व है अगर इनको बंद किया जाये तो सारा काला धन बाहर आ सकता है व भारत में चल रहे जाली नोटों के व्यापार को रोक कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले राजनेताओं व नौकरशाहों को सत्ता के तंत्र से बाहर किये बिना कोई भी पहल सार्थक नहीं होगी। इसलिए देश को मजबूत नहीं मजबूत प्रधानमंत्री व उस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होगी। मात्र सत्ता परिवर्तन से भ्रष्टाचार का अन्त नही होगा। पूर्व मे हुये प्रयोग इसके प्रमाण हैं लेकिन बदलाव में यदि राजा बाधा उत्पन्न करता है तो पहले उसे बदलना है। इसलिए वर्तमान में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है पर उसके साथ ही एक जन दबाव भी सत्ता तंत्र पर हमेशा बना रहे।

सत्ता परिवर्तन के साथ ही भ्रष्टाचार की जननी वर्तमान में चल रही व्यवस्था तंत्र में भी बदलाव लाना होगा। व्यवस्था परिवर्तन की एक व्यापक बहस देश में प्रारम्भ करनी होगी। जो व्यवस्था समाज में विषमता को बढ़ावा देती हो, शोषणकारी हो उसे बदलना आवश्यक हो जाता हैए हमें भारत केन्द्रित चुनाव प्रणाली, न्याय, प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा। सभी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही समाज में व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को भी बल प्रदान करना होंगा। यानि संस्कार व नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने के प्रयास तेज करने होगें। तभी इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को हम समाप्त कर भारत को पुनः दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक गुरू के रूप में स्थापित कर पायेंगे।

(लेखक : अ.भा. विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री हैं)

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अक्टूबर अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसमायिक घटनाक्रमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें नीचे दिये गये संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें-

"छात्रशक्ति भवन"
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005.
फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाइट : www.abvp.org

झुका लविवि प्रशासन, कापी दिखाने को राजी

लखनऊ। अभाविप के आन्दोलन के आगे लखनऊ विवि प्रशासन बैकफुट पर आ गया। विवि सभी फेल छात्रओं की कापी दिखाने को राजी हो गया। अभाविप कार्यकर्ता, आईटी, के.क.वी. कालेज के बीएससी तथा बीए प्रथम वर्ष के कापी दिखाने की मांग पर लविवि के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे थे।

काफी देर तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मिलने या बातचीत के लिए नहीं आया, लेकिन अभाविप कार्यकर्ता देर तक धूप में बैठे रहे। बाद में बढ़ते दबाव को देखते हुए लविवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. यशवीर त्यागी आए और छात्र-छात्राओं को बताया कि प्रशासन छात्राओं की कापियाँ दिखाने को राजी हो गया है। त्यागी ने कहा कि विद्यार्थी के साथ-साथ उसके अभिभावक तथा कालेज के अध्यापक भी कापी देख सकेंगे।

उनका यह निर्णय कि कापी दिखाने के ५०० रुपए देने होंगे को भी अभाविप ने नकार दिया। तानाशही रवैया अपनाने वाले लविवि के अधिकारी इसे जरुरी बताने पर अड़े रहे। अभाविप लविवि के इस निर्णय को छात्रों से वसूली का एक नया पैतरा मानती है। वह समस्या सुलझाने के बजाय उसे और जटिल करने पर उतारु है।

अभाविप के विभाग संगठन मंत्री मिथिलेश त्रिपाठी ने लविवि की इस वसूली को गैर जिम्मेदाराना बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि क्या लविवि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है। छात्रों को कापी दिखाने के उसके फैसले को लविवि ने ताक पर रख दिया है। जहाँ आटीआई में १० रुपए के शुल्क के साथ आवेदन करने पर पहले घंटे दस्तावेज निःशुल्क देखे जा सकते हैं वहीं लविवि कापी दिखाने के ५०० रुपए किस बात के ले रहा है। छात्राओं के आरटीआई आवेदन पर अभी तक वह कोई फैसला नहीं ले सका है। अभी एक महीने पहले भी लाला महादेव प्रसाद गर्ल्स कालेज की छात्राओं ने भी आरटीआई के तहत कापियाँ दिखाने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि लविवि से ही संबद्ध नेशनल कालेज अपनी छात्रों की कापियों को दिखाने की व्यवस्था किए हुए है। लेकिन लविवि उससे सीखने के बजाय प्रक्रिया को ही दोषी ठहरा रहा है।

लविवि में अभाविप के जिला संयोजक रोहित सिंह ने इस फैसले को छात्रों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर लगातार शुल्क में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। और दूसरी ओर छात्रों के साथ धोखा हो रहा है।

सत्ता नहीं, समाज के बदलने से मिटेगा भ्रष्टाचार

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने देश की भ्रष्ट व्यवस्था पर जोरदार प्रहार किए। वक्ताओं ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए युवाओं का आगे आने का आह्वान किया गया।

संगोष्ठी में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त, श्री नीतिन व्यास पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेश ठाकुर और श्री आर.के. बावा उपस्थित थे।

वक्ताओं ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की लिस्ट में आए दिनों नए मामले जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश के हर नागरिक को आगे आना होगा। भ्रष्टाचार सत्ता नहीं बल्कि समाज के बदलने से समाप्त होगा। देश व समाज को बदलने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना होगा। आज आजादी के ६३ साल बाद भी व्यवस्था में बदलाव नहीं आया है। देश को विकसित करने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था का सुधार करना होगा।

संगोष्ठी में पांच सौ से अधिक विद्यार्थियों एवं युवाओं ने भाग लिया।

समग्र क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण

एक अभूतपूर्व मंथन से हम सब और हमारा देश पिछले कई सालों से गुजर रहा है। इस वक्त, जबकि हम इस मंथन के एक पड़ाव पर आकर खड़े हैं, अवश्कता है इसके सिंहावलोकन की, कुछ निरीक्षण-परीक्षण, लेखा-जोखा और मुल्यांकन की। जनजीवन में समय-समय पर आने वाले ऐसे ज्वार और मंथन का सम्यक आंकलन कर सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया गया। १९७४ में गुजरात के छात्रों ने निर्णायक लड़ाई लड़कर यह साबित कर दिखाया कि भारत की छात्र-शक्ति, 'समलक्ष्य' और 'समबोध' के रास्ते पर आगे बढ़कर उन मूल्यों को स्थापित करने के लिये प्रभावी भूमिका अदा कर सकती है, जिनके लिये आजादी की लड़ाई लड़ी गयी थी। बिहार के छात्रों ने अपनी नौजवानी और पुरुषार्थ के तकाजों को अमलीजामा पहनाने के लिये 'खाद्यान्न की कमी, वस्तुओं के अभाव, मूल्य वृध्दि, कालाबाजारी, गरीबी, अनुपयोगी शिक्षा नीति, बेकारी और भ्रष्वाचार' के विरोध में आगे बढ़कर गुजरात की संघर्ष पताका को थाम लिया। बिहार का ऐतिहासिक छात्र आन्दोलन उपर्युक्त मांगों से प्रारम्भ होकर नव-बिहार के निर्माण, लोकतंत्र के स्थायित्व और विकेन्द्रीकरण की राह से चलता हुआ 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के जरिये देश के नवनिर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ। सम्पूर्ण क्रान्ति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होने भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये किया था। लोकनायक ने कहा कि सम्पूर्ण क्रांति में सात क्रांतियाँ शामिल है- राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन सातों क्रांतियों को मिलाकर सम्पूर्ण क्रान्ति होती है।

सम्पूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केन्द्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पडा था। जयप्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी सम्पूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने-कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर-घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। आन्दोलन के दौरान सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी जाने पर यह स्पष्ट दिख पड़ता था कि यह एक जन आन्दोलन है। छात्र, अध्यापक, वकील, कर्मचारी, दुकानदार- व्यापारी, बच्चे-किशोर -युवा-अधेड़-वृध्द, पुरुष-महिला, भूखे-नंगे मजदूर- किसान से लेकर धनवान, लेखक-कवि-साहित्यकार-पत्रकार-विद्वान और सभी वर्ग के लोगों का जे.पी. के आन्दोलन के प्रति सहानुभूति और सहयोग भाव था। इन सबके अलावा जे.पी. के प्रति उनके मनों में था प्रबल और अप्रतिम विश्वास। जन सहानुभूति और जन विश्वास ही तो था कि पटना की रैलियों और सभाओं में लाखों लोग आते थे और पटनावासी अपने घरों से भोजन-जलपान तैयार कर लाते और उन्हें खिलाते थे, उनका स्वागत करते थे। पटना के प्रबुध्दजनों की राय में बिहार में इस प्रकार का जन आन्दोलन देखने में नहीं आया था। कुछ की राय तो यह थी कि ऐसा जन आन्दोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी नहीं चला। इसकी खास बात यह भी थी कि बिहार सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि पुलिस और बंदूकों की ताम-झाम और कवायद कराके ऐसी स्थिति-परिस्थिति उत्पन्न की जाये की आन्दोलन हिंसक हो उठे और संगीनों के जरिये उसे कुचला जा सके। लेकिन हुआ यह की हजारों-हजार सत्याग्रही सचिवालय, सरकारी कार्यालयों और सड़कों पर लेट जाते थे और सरकार की बंदूकें धरी की धरी रह जाती थीं।

पांच जून, १९७५ की विशाल सभा में जे.पी. ने पहली बार 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के दो शब्दों का उच्चारण किया। क्रान्ति शब्द नया नहीं था, लेकिन 'सम्पूर्ण क्रान्ति' नया था। पांच जून को सांयकाल पटना के गांधी मैदान पर लगभग पांच लाख लोगों

की अति उत्साही भीड़ भरी जनसभा में देश की गिरती हालत, प्रशासनिक भ्रष्टचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पध्दति और प्रधानमंत्री द्वारा अपने ऊपर लगाये गए आरोपों का सविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने बेहद भावातिरेक में जनसाधारण का पहली बार 'सम्पूर्ण क्रान्ति' के लिये आह्वान किया।

जे.पी. ने कहा- 'यह क्रान्ति है मित्रों! और सम्पूर्ण क्रान्ति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है।'

पांच जून को जे.पी. ने घोषणा की- भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रान्ति लाना, आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब सम्पूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। और, सम्पूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रान्ति- 'सम्पूर्ण क्रान्ति' आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वह सम्पूर्ण और बहुमुखी है, इसलिए इसका समाधान सम्पूर्ण और बहुमुखी ही होगा। व्यक्ति का अपना जीवन बदले, समाज की रचना बदले, राज्य की व्यवस्था बदले, तब कहीं बदलाव पूरा होगा, और मनुष्य सुख व शान्ति से मुक्त जीवन जी सकेगा।

जे.पी. ने छात्रें से सम्पूर्ण क्रान्ति को सफल बनाने के लिए एक वर्ष तक विश्वविद्यालयों और कालेजों को बंद रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि- 'केवल मंत्रिमंडल का त्याग पत्र या विधानसभा का विघटन काफी नहीं है, आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है। छात्रों की सीमित मांगें- जैसे भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी का निराकरण, शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आदि बिना सम्पूर्ण क्रान्ति के पूरी नहीं की जा सकती।' उन्होंने सीमा सुरक्षा बल और बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों से अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दें।

जे.पी. ने सात जून से बिहार विधानसभा भंग करो अभियान चलाने, मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभा के फाटकों पर धरना देने, प्रखण्ड से सचिवालय स्तर तक प्रशासन ठप्प करने, लोकशक्ति को बढ़ाने हेतु छात्र-युवक एवं जन संगठन बनाने, नैतिक मूल्यों की सदाचरण द्वारा स्थापना करने तथा गरीब और कमजोर वर्ग की समस्याओं से निपटने के लिए भी छात्रों एवं जनसाधारण का आह्वान किया।

सात जून को जे.पी. का भाषण जब समापन की ओर था तभी सभास्थल पर गोलियों से घायल लगभग १२ लोग पहुंचे और सभा में तीव्र उत्तेजना फैल गई। ये राजभवन से लौटने वाली भीड़ के वे लोग थे जो पीछे रह गए थे। इन लोगों पर बेली रोड स्थित एक मकान से गोली चलाई गई थी। पटना के जिलाधीश विजयशंकर दुबे के अनुसार- उस मकान में 'इन्दिरा ब्रिगेड' नामक संगठन के कार्यकर्ता रहते थे। उनमें छह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से एक के पास से धुआं निकलती बन्दूक और छह गोलियां बरामद की गई हैं। सभा में जिलाधीश द्वारा लिखा गया पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करने तथा गोलीकाण्ड के बावजूद प्रदर्शनकारियों द्वारा शान्ति और संयम बरतने की सराहना की गई थी। विशाल जनसमूह के लोग गोलीबारी से चोट खाए लोगों को देखकर इस हद तक उद्वेलित हो उठे थे कि यदि जे.पी. को दिया गया शान्तिपूर्ण रहने का वचन न होता और स्वयं जे.पी. वहां मौजूद न होते, तो शायद उस शाम इन्दिरा ब्रिगेड के दफ्तर से लेकर विधान सभा-सचिवालय आदि, सब कुछ जल गया होता।

सभा स्थल पर जे.पी. ने कहा- 'देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग धारा में बह जाएं, उस स्थान पर जाकर आग लगा दें। वचन देते हो न कि शान्त रहोगे?' लाखों ने हाथ उठाकर, सिर हिलाकर और 'हां' की जोरदार आवाज लगाकर जे.पी. को वचन दिया। प्रदर्शनकारियों और आम जनता ने- 'हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा' के नारे का वस्तुतः पालन करके जे.पी. को दिखा दिया। लोग एकदम शान्त हो गये, ऐसा था जे.पी. का प्रभाव और उनके नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन का अनुशासन।

बिहार छात्र आन्दोलन का चौथा चरण सात जून, १९७४ से जयप्रकाश नारायण के इस

आह्वान के अनुसार प्रारम्भ हुआ कि 'हमें सम्पूर्ण क्रान्ति चाहिए, इससे कम नहीं।' 'विधानसभा भंग करो।' के स्थान पर 'विधान सभा भंग करेंगे' के नारे के साथ अहिंसक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह, धरना आदि का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

जे.पी. द्वारा निर्देशित आन्दोलन के कार्यक्रमों में विधानसभा भंग करने का अभियान चलाना, विधानसभा के सभी फाटकों पर सत्याग्रह और धरना आयोजित कर सदस्यों को अन्दर न जाने देना, सचिवालय से लेकर ब्लाक स्तर तक प्रशासनिक कामकाज एकदम ठप्प कर देना, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन, सत्याग्रह कर जेल जाना और छात्र संघर्ष समिति द्वारा विधायकों के इस्तीफे की मांग शामिल था।

राजनीतिक क्षेत्र में जे.पी. सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। वे चाहते थे कि प्रत्याशियों का चयन तथा राजसत्ता पर नियंत्रण जनता के द्वारा होना चाहिए। वे लोक चेतना के द्वारा जनता को जगाकर उसे लोकतंत्र का प्रहरी बनाना चाहते थे ताकि नीचे के कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सबके काम काज पर निगरानी रखी जा सके। वे चाहते थे कि जन प्रतिनिधियों को समय से पूर्व वापस बुलाने का अधिकार उस क्षेत्र की जनता को मिले ताकि जन प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मार्च, १९७४ में प्रारम्भ हुए बिहार छात्र आन्दोलन का दौर १५ महीने रहा। १८ महीने की इमरजेंसी आई। भारत की लोकसभा के चुनाव घोषित हुए, जिसे आन्दोलन समर्थकों ने जे. पी. के नेतृत्व में 'लोकशाही बनाम तानाशाही' को मुद्दा बनाकर लड़ा। इमरजेंसी की आकस्मिक घोषणा के फलस्वरूप 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की संघर्ष-यात्रा 'लोकतंत्र के रक्षा-अभियान' में बदल गयी और सरकार को हटाना ही 'सम्पूर्णता लक्ष्य' बन गया। १९७७ के चुनाव नतीजों ने सिध्द कर दिया कि जे. पी. के आन्दोलन के प्रति जनता की पूरी सहमति और स्वीकृति थी।

पटना मे अपने विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम मे भी भाग लिया और जेल भी गए। १९२२ मे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने १९२२-१९२९ के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-बरकली, विसकांसन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यन किया। पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्होंने खेतों में ट्रेक्टर चलाने से लेकर रेस्ताराओं में भी काम किया। जीवन भर शाकाहारी रहे जयप्रकाश नायरायण को अमरीका में गायों के कत्लखाने में भी काम करना पड़ा था। उन्होने एम.ए. की डिग्री प्राप्त की लेकिन गाँव में माताजी की तबियत ठीक न होने की वजह से वे १९२९ में भारत वापस आ गए और पी.एच.डी की आस अधूरी रह गई।

शिक्षा के संबंध में जे.पी. का कहना था कि शिक्षा बुनियादी रूप से वही रह गई जो अंग्रेजी शासन काल में थी। वे वर्तमान शिक्षा प्रणाली को गुलाम बनाने वाली तथा क्लर्क पैदा करने वाली मानते थे। वो स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय को छात्रों का भविष्य और समय बर्बाद करने वाली संस्थाएं बताते थे। वे शिक्षा को डिग्री तथा परीक्षा से अलग रखने के पक्षधर थे। जे.पी. शिक्षा में श्रम की महत्ता स्वीकार करते थे। जे.पी. चाहते थे कि बच्चों का दाखिला भले ही टेस्ट के आधार पर लिया जाए, लेकिन जितने भी वर्ष का पाठयक्रम हो उसके भीतर ही उपस्थिति के आधार पर छात्रों को डिग्री प्रदान की जाए।

जे.पी. क्रान्ति के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास चाहते थे तथा विकास की प्रक्रिया की शुरूआत भी उसी अंतिम व्यक्ति से करना चाहते थे। इस चीज के लिए उन्होंने एक नया शब्द खोजा था- 'अंत्योदय'। यानी जो सबसे गरीब और असहाय है उसकी चिन्ता पहले की जाए और उसका उदय सबसे पहले हो।

समता, स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नए समाज की रचना चाहते थे ताकि एक नए मनुष्य का निर्माण हो सके। वे क्रान्ति का सूत्रपात गांव से करना चाहते थे। उनका मानना था कि गांव की हर एक समस्या का चिन्तन ही सम्पूर्ण या समग्र क्रान्ति का पहलू है। इसलिए रचना, संघर्ष, शिक्षण और संगठन की चतुर्विधि प्रक्रिया से वो गांवों को बदलना चाहते थे। उनका कहना था कि जब गांव बदलेंगे तो शहर भी बदले बिना नहीं रहेंगे।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

जानें अपने हक़,
मांगें अपने हक़

बृजेन्द्र प्रताप सिंह
राज्यमंत्री,
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा
के लिए कटिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार

5 दिन में
खसरे की नकल मिलना।

7 दिन में
स्थानीय निवासी का
प्रमाण पत्र मिलना।

7 दिन में
हैंडपंप का सुधार होना।

11 दिन में
नया बिजली कनेक्शन
प्राप्त करना।

15 दिन में
भू-अधिकार पुस्तिका मिलना।

30 दिन में
प्रसूति योजना का
लाभ प्राप्त करना।

30 दिन में
नल का कनेक्शन मिलना।

30 दिन में
नया राशन कार्ड बनना।

60 दिन में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना।

जनसंपर्क मध्यप्रदेश द्वारा जारी

आर.एन.आई. नं. 32464/78
Con.No-DL (N)/249/10-12

आईआईटी रुडकी में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनरत अभाविप कार्यकर्ता

कोलकाता कार्यालय का उद्घाटन करते हुए मा. दत्तात्रेय होसबाले

ABVP

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad